

बिम्बा संवाददाता

देवघर। सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर और बाबा बासुकीनाथ धाम, दुमका में सोमवारी के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए हैं। भगवान बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा गुलाब नंद झा ने कहा कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन की सोमवारी को बाबा पर जल, बेलपत्र और सच्ची आस्था के साथ जलाभिषेक करने की धार्मिक मान्यता है। इसी आस्था के कारण अंतिम सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचे हैं। देवघर के उपालुक्त सीरम कुमार भुवनिग्या ने बताया कि पिछली सोमवारी की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक है। प्रशासन की ओर से सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार नियमानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि रात से ही पुलिसकर्मों और पदाधिकारी श्रद्धालुओं को काराबन्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराने में जुटे हैं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखा जा रही है। अंतिम सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट सुबह 4.30 बजे खोला गया। पट खुलते ही हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के शिवलिंग पर जलापत्र शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। अंतिम सोमवारी के अवसर पर राज्य की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदारा मिश्रा भी देवघर पहुंचीं और बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। सावन की अंतिम सोमवारी पर दुमका जिले के प्रसिद्ध फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बोल बम कार्रवायों के साथ भागलपुर के बरारी घाट से गंगाजल लेकर हंसडीहा के रास्ते पहुंचने वाले बड़ी संख्या में डाकबम श्रद्धालु भी बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन पहले से ही पूरी तरह चौकस है। मंदिर के प्रवेश द्वार निकास द्वार तथा मेला क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। झोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। बासुकीनाथ मंदिर का पट सुबह तीन बजे खोला गया। इसके बाद श्रद्धालुओं की काराबन्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया गया और अरघा के माध्यम से जलाभिषेक कराया गया। हंसडीहा के रास्ते पहुंचने वाले डाकबम श्रद्धालुओं को टोकन देकर पेड़ा गली द्वार से सीधे मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। झारखंड सहित अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं में बाबा बासुकीनाथ के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, बाबा बैद्यनाथ धाम में अब तक 52 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा पर जल चढ़ा चुके हैं।

Page 10 of 10

झारखंड में अगले माह से शुरू होगा एयर होस्टेस और ग्राउंड क्रू का प्रशिक्षण

चयन साक्षात्कार संपन्न

जेपीसी की अहम बैठक.

बिभा संवाददाता
गुंजी। दारुमंद सरकार के नाम
 व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध
 कराकर उन्हें विपन्न उद्योग की
 व्यक्ति विकास और उद्योग
 समर्थन कौशल से सम्पन्न

खिमा संवाददाता

सुकमा। डोहासिगढ़ नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के भण्डारपरदे के जंगल-पहाड़ी इलाके में जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प का भंडापोट किया है। मौके से 23 हथियार, 492 जिंदा कारतूस और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। कार्रवाई 24 अगस्त 2026 को आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस से आधार पर की गई।

पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने आज शाम एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि भण्डारपरदे के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा हथियार एवं विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें डम्प का पता लगाकर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें 23 हथियार, 492 जिंदा कारतूस और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामदगी में एके-47, एसएलआर, ईसास समेत विभिन्न हथियारों के साथ 240 जिलेटिन स्टिक, 18 किलो गन पाउंडर और 5 देशी हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। यह कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने की।

वेटलैंड क्षेत्रों के संरक्षण, सीमांकन और बेहतर प्रबंधन आवश्यक : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

बिश्मा संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य आद्रभूमि (वेटलैंड) प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें राज्य के वेटलैंड क्षेत्रों के संरक्षण, सीमांकन और बेहतर प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राज्य में अवस्थित आद्रभूमि (वेटलैंड) को चिह्नित करने, उनका गहन अध्ययन एवं व्यवस्थित दस्तावेजीकरण कराने और डिमांडेशन के बाद नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य की सभी आद्रभूमि की



सूची तैयार करने और उसका नियमित अद्यतन, आद्रभूमि का डेटाबेस विकसित तथा संधारित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित वेटलैंड की पहचान से लेकर सत्यापन, डिमांडेशन, नोटिफिकेशन, दस्तावेजीकरण और मैनेजमेंट प्लान

तक की प्रक्रिया राज्य के प्राकृतिक जल क्षेत्रों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेटलैंड जल क्षेत्र के साथ-साथ राज्य की जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनके संरक्षण के लिए गहन अध्ययन

और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रभावी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने वेटलैंड की वर्तमान स्थिति, जल स्रोत, आसपास की गतिविधियों और समय के साथ हुए बदलावों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने पर बल दिया।

बैठक में राज्य के पर्यावरण, जल स्रोतों और जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य की सभी प्रमुख आद्रभूमियों के संरक्षण, सीमांकन और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग तथा भूमि राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना और जल संकट से निपटने के लिए प्राकृतिक जल निकायों का जीर्णोद्धार करना है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इससे से प्राप्त एटलस के आधार पर झारखंड में 2119 संभावित वेटलैंड की सूची प्राप्त हुई है। अब इन संभावित स्थलों का जिला स्तरीय आद्रभूमि समितियों की ओर से भौतिक एवं तथ्यात्मक सत्यापन किया जाएगा। साथ

ही आद्रभूमि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने, अतिक्रमण की रोकथाम, गतिविधियों का विनियमन और राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बाद राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से वेटलैंड की पहचान एवं सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चिह्नित वेटलैंड का डिमांडेशन कर नोटिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक महत्वपूर्ण वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुसार मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया।

सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालियों में उमड़ी आस्था, पहाड़ी मंदिर में 1.50 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक



बिश्मा संवाददाता

रांची। सावन की अंतिम सोमवारी पर राजधानी के शिवालियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पहाड़ी मंदिर में करीब 1.50 लाख श्रद्धालुओं ने अरघा सिस्टम से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सरकारी पूजा के बाद सुबह 3.30 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भक्तों ने दूध, गंगाजल, फूल और माला अर्पित कर पूजा-अर्चना की।

सुरेश्वर धाम, इक्कीसों धाम चुटिया, लिंगेश्वर मंदिर मधुकम और अरगोड़ा बुढ़ा महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों की कतार लगी रही। कांवरिये स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार रातू रोड तक पहुंच गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद रही। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजते रहे।

चेंबर चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेवारी

बिश्मा संवाददाता

रांची। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को चेंबर भवन में चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए चेंबर कार्यालय को विभिन्न कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। चुनाव समिति के निर्देश के क्रम में चेंबर के सभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन लॉक कर दिया गया। अब इन ऑफिशियल ग्रुपों के माध्यम से केवल चुनाव से संबंधित आवश्यक सूचनाएं और गतिविधियों की जानकारी ही जारी की जाएगी।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर ने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान चेंबर भवन में किसी भी प्रत्याशी की ओर से चुनावी बैठक अनाधिकृत नहीं की जाएगी। साथ ही व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित किसी भी गतिविधि का आयोजन चुनाव समिति की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को



निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए समिति की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सह अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि 12 अगस्त 2026 को संपन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिन सदस्यों को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, उन्हीं को आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार होगा।

संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अब सदस्यता में प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। चुनाव से पूर्व केवल संबद्ध संस्थाओं के पदाधिकारियों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य श्रेणी के सदस्यों के प्रतिनिधि के नाम में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुनाव समिति ने सभी सदस्यों से चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने और समिति की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की।

नगर निगम ने तीन आरओ प्लांट पर टोका 1.50 लाख का जुर्माना

बिश्मा संवाददाता

रांची। शहर में भूगर्भ जल के अनधिकृत दोहन और अवैध जलापूर्ति गतिविधियों के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की जलापूर्ति शाखा ने सोमवार को तीन आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। जांच में तीनों इकाइयों का संचालन बिना वैध लाइसेंस के पाए जाने पर प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का ऑन-स्पॉट जुमाना लगाया गया। तीनों प्रतिष्ठानों से कुल 1.50 लाख रुपये का जुमाना वसूला गया।

निगम की टीम ने गो जल आरओ, मोरहाबादी सरना टोली, मां पानी सर्विस आरओ वाटर, चिरौड़ी-बोड़िया रोड एवं आरवी आरओ वाटर, कुसुम बिहार, मोरहाबादी की जांच की।

निगम के अनुसार, नियमों के तहत अनुज्ञापित के बिना संचालन किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने सभी आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों से आवश्यक दस्तावेजों

के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा है। इसके लिए आधार कार्ड, कंपनी/फर्म का पंजीकरण प्रमाण, छिद्रान बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स रसीद, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण का एनओसी और फोटो सहित वर्षा जल संचयन संरचना का विवरण देना होगा।

लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये और नवीकरण के लिए 20 हजार रुपये शुल्क निर्धारित है। अब तक निगम को करीब 90 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर आगे भी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध जल संयोजन और भूगर्भ जल के अनधिकृत दोहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

जलापूर्ति संबंधी शिकायत के लिए निगम के टोल फ्री नंबर 1800 570 1235 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री से टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात



रांची(बिभा)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से सोमवार को कांकि रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट सर्विसेज, टाटा स्टील डीबी सुंदरारामन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मौके पर रेजिडेंस एगिजक्युटिव, टाटा स्टील अरविंद कुमार सिंह उपस्थित रहे।

रिम्स अकादमिक परिषद की बैठक में शैक्षणिक विस्तार और नए कोर्स पर मंथन



रांची(बिभा)। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अकादमिक परिषद की बैठक में संस्थान के शैक्षणिक और ढांचागत विस्तार को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे गए। इसमें मुख्य रूप से 250 एमबीबीएस सीटों के अनुसार विभागों में फैकल्टी और संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में 'इंटीग्रेटेड एमडी-पीएचडी', एमएससी नर्सिंग और क्रिटिकल केयर में बैचिक डिप्लोमा जैसे नए कोर्स शुरू करने की योजना बनाई गई। इसके अलावा, जूनियर रेजिडेंट की संख्या बढ़ाकर 150 करने, मनोरोग विभाग व नशामुक्ति केंद्र को सुदृढ़ करने और रेडियोथेरेपी तथा ब्लड सेंटर विभागों के नाम बदलने का भी प्रस्ताव रखा गया। इन सभी कदमों का मुख्य उद्देश्य रिम्स में मेडिकल शिक्षा के मानकों को पूरा करना और मरीजों के इलाज की सुविधाओं को और अधिक उन्नत बनाना है।

वंदे मातरम का विरोध नहीं, राष्ट्रभावना का सम्मान जरूरी: संजय सर्राफ

रांची(बिभा) : हिंदी साहित्य भारती के उपाध्यक्ष सह विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के प्रांतीय प्रवक्ता संजय सर्राफ ने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत ने करोड़ों भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाने और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का साहस पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े गीत का अनावश्यक विरोध निश्चित रूप से उचित नहीं माना जा सकता। वंदे मातरम के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय थे। उनके उपन्यास आनंदमठ में यह गीत प्रकाशित हुआ था। बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रेरणास्रोत बना। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के दौर में वंदे मातरम देशवासियों के लिए संघर्ष और एकता का उद्घोष बन गया।



संविधान सभा ने भी 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्रदान किया। भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग-अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति का अर्थ किसी धर्म या समुदाय विशेष से जोड़ना नहीं, बल्कि संविधान, तिरंगे, मातृभूमि और देश की एकता-अखंडता के प्रति सम्मान रखना है। इसी भावना से वंदे मातरम को भी देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी गीत के प्रति अपनी व्यक्तिगत मान्यता या असहमति रखने का अधिकार हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े प्रतीकों का सार्वजनिक रूप से अपमान या अनावश्यक विरोध सामाजिक सद्भाव के लिए उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाएं और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। आज जब देश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हमें ऐसे प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए जो स्वतंत्रता संघर्ष की याद दिलाते हैं। वंदे मातरम का सम्मान किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता चेतना और राष्ट्रीय गौरव का सम्मान है।

25 अगस्त से राज्यभर में शुरू होगा होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे:के. रवि

बिश्मा संवाददाता

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों का सत्यापन करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही परिवार एवं एक ही घर में निवास करने वाले मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हों तथा कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गरीब पुनरीक्षण (रस्क) के तहत 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बाद अब घर-घर सत्यापन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र



भारतीय नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है अथवा जिनका नाम दर्ज नहीं है, उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं घोषणापत्र जमा किया गया है और उसका डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान बीएलओ यह भी देखेंगे कि एक परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में तो दर्ज नहीं हैं। यदि किसी मतदाता का नाम उसके सामान्य निवास से संबंधित मतदान क्षेत्र के निर्धारित मतदान केंद्र के स्थान पर

किसी अन्य मतदान केंद्र में दर्ज है, तो उसे संबंधित मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 भरने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक परिवार-एक मतदान केंद्र की व्यवस्था को प्रभावी बनाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में सामान्य रूप से निवास करने वाले ऐसे मतदाता, जिनका नाम वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और जो अपना नाम झारखंड के वर्तमान सामान्य निवास वाले

मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 के साथ निर्धारित घोषणापत्र जमा कर सकते हैं। बीएलओ ऐसे पात्र मतदाताओं को भी आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे। के. रवि कुमार ने बताया कि होम टू रोल वेरिफिकेशन के दौरान सभी परिवारों में 'Family Together Sticker' लगाने की भी पहल की जाएगी। इस स्टिकर के माध्यम से परिवार से यह सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी कि परिवार के सभी वयस्क एवं पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं। स्टिकर पर संबंधित घर/नजरी गृह संख्या अंकित करने की व्यवस्था के साथ मतदाताओं की सहायता के लिए बीएलओ से संपर्क का प्रावधान भी रहेगा। यह कार्य 4 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भाजपा का बयान हताशा का परिचायक : विनोद कुमार पांडेय

बिश्मा संवाददाता

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुो) के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्षी आवाजों को लेकर झारखंड सरकार को नसीहत देने से पहले अपने शासन वाले राज्यों का हिसाब दे। उन्होंने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा के बयान को हताशा का परिचायक बताया।

विनोद पांडेय ने कहा कि झारखंड सरकार की तुलना इतिहास की गंधी त्रासदियों से करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। धरना-प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था और सोशल मीडिया नियमों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कोई अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक दमन बताना भ्रामक है। जेपीएससी मामले पर उन्होंने कहा कि न्यायालय में सरकार की ओर से कौन अधिवक्ता किस स्तर पर पैरवी



करेगा, यह विधिक प्रक्रिया का विषय है। भाजपा के पास ठोस तथ्य या दस्तावेज हैं तो उसे सक्षम न्यायालय में रखना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अपने शासन वाले राज्यों में छात्रों, किसानों और विपक्षी नेताओं के साथ हुए व्यवहार का लेजर सवाल उठाते हुए कहा कि रोजगार के लिए भाषा को डर और दंड का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा से पूछा कि क्या अब हर राज्य में रोजगार के लिए स्थानीय भाषा की परीक्षा होगी। पांडेय ने कहा कि भाजपा को विकास, अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर तथ्यपूर्ण राजनीति करनी चाहिए।

केंद्र पर आरोप लगाने से पूर्व अपनी अवैध खनन पर जवाब दे राज्य सरकार : सेठ

बिश्मा संवाददाता

रांची। झारखंड में एमएमआरडी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जारी पुनरीक्षण के बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कोयले पर लगाए जा रहे राज्य स्तरीय करों, सेस और शुल्क एवं अवैध खनन को लेकर सरकार से जवाब मांगा। सेठ ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले राज्य सरकार को अपनी टेक्स व्यवस्था और अवैध खनन पर जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि झारखंड में कोयले का मूल मूल्य करीब 1,221 रुपये प्रति टन है, लेकिन विभिन्न राज्य करों और शुल्कों के कारण बिक्री कीमत करीब 2,458.78 रुपये प्रति टन पहुंच जाती है। इसके मुकाबले पश्चिम बंगाल में कीमत करीब 1,741.22 और ओडिशा में 1,708.48 रुपये प्रति टन बताई गई।

सेठ ने कहा कि इससे झारखंड का कोयला पड़ोसी राज्यों की तुलना में करीब 700-750 रुपये प्रति टन महंगा पड़ रहा है।



रक्षा राज्य मंत्री ने मैनेजमेंट फीस, मिनरल सेस, रॉयल्टी आधारित शुल्क, फरिस्ट ट्रांजिट फीस, कंपोजिट यूजर फीस और बाजार फीस सहित अन्य शुल्कों को कोयले की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले अवैध खनन पर रोक लगाए। साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने डीएमएफ के माध्यम से झारखंड के खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 19 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने डीएमएफ राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं पर भी सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

जनता दरबार में दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल

बिश्मा संवाददाता

रांची। जिला डंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजनजी ने सोमवार को समाहणालय में आयोजित जनता दरबार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमजनों को शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

जनता दरबार में दिव्यांग कार्तिंक खलखो ने आवागमन में परेशानी



बताते हुए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की मांग की। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार को हो रही कठिनायियों को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल उन्हें

इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की। साथ ही दिव्यांगता पेंशन के लिए आवेदन भी लिया गया। ट्राईसाइकिल की चाबी मिलने पर कार्तिंक के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ नजर आई।

रातू के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग ने पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका जताई। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के कर्मों से जानकारी लेकर राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया और पात्र लाभुक को खानान एवं योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा।

अनगड़ा की निर्मला इंदवार ने बहन की इलाज के दौरान मौत में चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई

का निर्देश दिया और आवेदिका को एसएसपी के समक्ष शिकायत देने को कहा।

सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक बसंत कुमार साहू के लंबित पेंशन पुनरीक्षण मामले में भी यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जमीन, दाखिल-खारिज, दोहरी जमाबंदी, पंजी-2 में सुधार, अवैध कब्जे और बीएसएनएल टावर से जुड़े मामले भी आए। उपायुक्त ने कहा कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं. : ईएन-48-26, दिनांक 20.08.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा ख्यातिप्राप्त निविदाकारों जिनके पास वैध विद्युत ठेकेदार का लाइसेंस है एवं निम्नलिखित कार्य को पूरा करने में वित्तीय रूप से सक्षम हैं, से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: कार्य का नाम एवं इसका स्थान: (क) आसनसोल मंडल - 07 स्टेशन पर 12 लिफ्ट लगाने की व्यवस्था (रानीगंज-01, जसीडीह-01, मधुपुर-01, दुर्गापुर-02, मानक-04, बासुकीनाथ-02, चित्तंरंजन-01)। (ख) लिफ्ट के लिए 02 वर्ष की वारंटी अवधि पूरा होने के बाद 05 वर्ष का व्यापक रखरखाव अनुबंध। (ग) इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाय पाट। निविदा मूल्य : रु. 5,74,33,684.80, निविदा कागजात का मूल्य : शून्य। बयाना राशि : रु. 11,48,700/-, कार्य के लिए सामान्य अवधि : 12 माह। बंध होने एवं खुलने की तिथि और समय : दिनांक 15.09.2026 को 11.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट : www.ireps.gov.in में देखा जा सकता है। www.ireps.gov.in पर भी देख सकते हैं। निविदा सूचना वेबसाइट www.e.indianrailways.gov.in पर भी देख सकते हैं। हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

जनजातीय गौरव उत्सव केवल मेला नहीं, संस्कृति और उद्यमिता को बाजार से जोड़ने का माध्यम : राज्यपाल

बिभा संवाददाता
हजारीबाग। श्री राम जानकी मठ, बड़ा अखाड़ा ठाकुरवाड़ी परिसर में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित आठ दिवसीय जनजातीय गौरव उत्सव-2026 का सोमवार को भव्य समापन हुआ। बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान, झारखंड की ओर से आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद, पलामू ब्रजमोहन राम शामिल हुए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। राज्यपाल के आगमन से समापन समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। समापन समारोह से पूर्व



राज्यपाल ने उत्सव परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों एवं प्रदर्शनी का भ्रमण किया। उन्होंने जनजातीय, महिला एवं स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों का अवलोकन किया तथा उद्यमियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। उत्सव में पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़,

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों एवं महिला उद्यमियों ने करीब 70 स्टॉल लगाए थे। इनमें महिलाओं द्वारा तैयार कपड़े, अचार, हस्तशिल्प, सजावटी सामान, धरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा पारंपरिक उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र

रहे। समारोह में उत्कृष्ट महिला एवं जनजातीय उद्यमियों के आठ समूहों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल का आयोजन समिति की ओर से अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया गया। मंच पर राष्ट्रीय एवं राष्ट्रगान के बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि इस तरह के आयोजन महिलाओं को अपने हुनर और उत्पादों को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे

आयोजन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव उत्सव केवल मेला नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों को जोड़ने और देश की सांस्कृतिक विरासत को बाजार से जोड़ने का माध्यम है। हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला, परंपरा और संस्कृति की पहचान हैं। महिलाओं की उद्यमिता केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से सशक्त बनने और समाज में अपनी पहचान

बनाने का माध्यम भी है। राज्यपाल ने कहा कि बदलते बाजार के अनुरूप गुणवत्ता और नई तकनीक पर ध्यान देना जरूरी है। कौशल के साथ तकनीक का इस्तेमाल कर उद्यमी बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए लोकल अभियान से जुड़कर महिलाएं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य होना चाहिए। युवाओं को भी कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।

उपायुक्त संदीप कुमार ने किया अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास का निरीक्षण



बिभा संवाददाता
लातेहार: उपायुक्त संदीप कुमार ने आज अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास का निरीक्षण कर छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, विद्युत, शौचालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि छात्राओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने छात्रावास प्रबंधन को नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने तथा छात्राओं की पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने छात्रावास भवन की आवश्यक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता को देखते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को छात्रावास के जीर्णोद्धार हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, संबंधित अधिकारी एवं छात्रावास प्रबंधन के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पेलावल ओपी क्षेत्र में चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, जेवर, नकदी और मोबाइल बरामद



बिभा संवाददाता
हजारीबाग: हजारीबाग जिले के पेलावल ओपी क्षेत्र में घर में चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त 2026 को ग्राम छड़वा, पंचायत रोमी निवासी प्रदीप राणा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। तकनीकी

साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद मेहताब और मोहम्मद शमीर कुंरेशी को गिरफ्तार किया गया। दोनों हजारीबाग के मांडई कला, लोहसिंधना थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद सोने का कान का टॉप, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र , घड़ी 5, नकद 55,750, बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, टीम ने मामले का सफल उद्घेदन कम समय में किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

संक्षिप्त खबरें

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित
रामगढ़(बिभा): आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाना है। इसके सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ मो 0 तोफीकुल हसन की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय रामगढ़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंक के एनओ पीओ एओ मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधकों से अपने-अपने बैंक से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु प्रस्तुत करने तथा पक्षकारों को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ के सचिव अनिल कुमार, रामगढ़ जिला के अग्रणी जिला प्रबंधक देवनारायण उराउई सहित अनेक बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ द्वारा बैंक के शाखा प्रबंधकों से अपील की गई कि वे आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से योग्य मामलों के शीघ्र एवं सरल समाधान के लिए आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।

सावण की अंतिम सोमवारी पर योगी सेना ने निकाली भव्य बाइक रैली

लोहरदगा(बिभा): जिले में सावण माह की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर योगी सेना लोहरदगा के तत्वावधान में भव्य बाइक रैली निकाली गई रैली लोहरदगा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नगर भ्रमण कर अखिलेश्वर धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूट्यूबर आदर्श गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं योगी सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा साथी बाइक रैली में शामिल हुए। रैली में श्रेयांस सिद्धार्थ (चीकू), प्रियांशु कुमार, नवीन कुमार, आशीष साहू, अनिकेत कुमार, गौरव कुमार, यशस्वी राज, आर्यमन केशरी, ऋत्विंक सिंह, अक्षत कुमार, नित्य राज, राजेश्वर सिंह, शुभ सोमिल, आर्यमान गुप्ता, गुप्ता सहित योगी सेना के अनेक युवा साथी मौजूद थे। सावण की अंतिम सोमवारी के अवसर पर निकाली गई इस बाइक रैली से पूरे लोहरदगा नगर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और युवाओं ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है।

संस्कार भारती ने हजारीबाग में आयोजित की मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता

हजारीबाग (बिभा)। अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती की हजारीबाग जिला इकाई द्वारा स्थानीय हिन्दू +2 उच्च विद्यालय में महिलाओं के लिए मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवारों में भारतीय सभ्यता और संस्कारों की पुनर्स्थापना करना था। इसका उद्घाटन संस्था की संरक्षिका डॉ. शोभा सहाय, प्रदेश कोषाध्यक्ष सीए विकास वर्मा, विभाग प्रमुख शंकर चंद्र पाठक और जिला अध्यक्ष कुमार केशव सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सामूहिक रूप से ध्येयगीत का गायन भी किया गया। प्रतियोगिता को तीन आयु वर्गों में बांटा गया था। रंगोली प्रतियोगिता के अलग-अलग वर्गों में उम्मुल साइमा, श्वेता कुमारी और मेघा राज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, मेहंदी प्रतियोगिता में श्वेता कुमारी, काजल कुमारी और नफीशा प्रवीन ने अपने-अपने वर्गों में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनके अलावा कई अन्य प्रतिभागियों ने द्वितीय, तृतीय और सात्वना पुरस्कार जीते। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका प्रवीण जायसवाल, संजय कुमार, रंजन कुमार दास और सीता देवी ने निभाई। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला मंत्री विनीत छाबड़ा (जैन) ने और धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष अनिल पाण्डेय ने किया। इस अवसर पर डॉ. अखौरी वीणा प्रसाद, सह मंत्री राजीव झा, राकेश रंजन, अविरल लाल, अमित गुप्ता और किशोर कुमार सिन्हा समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित थे।

उपायुक्त ने के.बी. महिला कॉलेज परिसर स्थित एससी-एसटी छात्रावासों का किया निरीक्षण,

बिभा संवाददाता
हजारीबाग: उपायुक्त हेमन्त सती ने आज सोमवार को के.बी. महिला कॉलेज, हजारीबाग परिसर का भ्रमण कर कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए संचालित महिला छात्रावासों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी छात्रावास भवनों का विस्तृत अवलोकन कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं एवं छात्राओं की आवश्यकताओं की जानकारी ली। के.बी. महिला कॉलेज परिसर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए कुल 05 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें लगभग 65 छात्राएं रह रही हैं। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने छात्रावास में रहने वाली समस्याओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। छात्राओं ने उपायुक्त को बताया कि



छात्रावास के किचन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। साथ ही, भवन की छत पर जल जमाव के कारण पानी के रिसाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर उपायुक्त ने स्वयं छात्रावास भवन की छत पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। छात्राओं द्वारा छात्रावास में आवश्यक बर्तन, पेयजल की सुविधा के लिए अतिरिक्त चापानल, बाउंड्री वॉल, सोलर लाइट की मरम्मत, शौचालय के गेट, पंखे सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। उपायुक्त ने छात्राओं की

मांगों पर सहमति प्रदान करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार कार्यों की स्वीकृति एवं शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्राओं की मूलभूत आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए तथा आवश्यक मरम्मत एवं निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

लातेहार में खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

बिभा संवाददाता
लातेहार। उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। उपायुक्त ने खनन क्षेत्रों और मार्गों पर सतत निगरानी बनाए रखने तथा विभागीय समयव्यय के साथ कार्रवाई करने पर जोर दिया। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने जानकारी दी कि 23 जुलाई 2026 से लेकर अब तक अवैध खनन उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया है। इस दौरान कुल 402 वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 40 टन खनिज और 8 वाहनों को जब्त किया गया है। उपायुक्त ने इस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए



संबंधित पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से औचक छापेमारी करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में संलग्न व्यक्तियों पर तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बालूघाटों के संचालन की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा की गई। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि नीलामी के बाद लातेहार अंचल के तुबेद, बाजकुम और राजहर बालूघाटों के निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हालांकि, वर्तमान में वर्षा ऋतु के कारण बालूघाटों का संचालन बंद है। शेष एक बालूघाट के निबंधन और चार अन्य बालूघाटों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा

रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन सामग्री लदा एक भी वाहन नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दक्षिणों को तुरंत पकड़कर एफआईआर दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, कोल कंपनियों के अधिकारी व प्रतिनिधि तथा सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे, जबकि सभी अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

जुलाई में सड़क हादसों में 8 मौतों पर डीसी ने जताई चिंता, महआडांड में चलेगा विशेष अभियान

बिभा संवाददाता
लातेहार। उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति, दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा उपायों की प्रगति और पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जुलाई माह में जिले में कुल 12 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 8 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन डरावने आंकड़ों पर उपायुक्त ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को पूरी



संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। हादसों पर लगाम लगाने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को घुमावदार सड़कों के किनारे टर्निंग

साइनेज, सड़क सुरक्षा साइनेज, रबल स्ट्रिप और जरूरी स्थानों पर सर्कुलर मिरर (गोल दर्पण) लगाने का निर्देश दिया। इससे वाहन चालकों को मोड़ और

सामने से आने वाले वाहनों की जानकारी समय रहते मिल सकेगी। साथ ही, घुमावदार सड़कों के बगल की झाड़ियां साफ करने और बरसात के

कारण हुए गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का सख्त निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने महआडांड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस करने को कहा है। इसके तहत रोज सेपटी टीम का सप्ताह में कम से कम एक दिन महआडांड जाकर जागरूकता अभियान चलाने, हेलमेट और प्रदूषण (ढवउ) जांच करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सड़क किनारे मौजूद अवरोधों और दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र पूरा करने को कहा गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हादसों को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ आम लोगों को जागरूक करना

भी बेहद जरूरी है। उन्होंने हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग और निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित अभियान चलाने पर जोर दिया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, सविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो, जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, विभिन्न थानों के प्रभारी, पथ निर्माण विभाग और एनएचआई के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, सभी अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

क्रिकेट के बहाने सत्ता, सुरक्षा और कूटनीति का अंदरूनी सच



कुमार कृष्णन

पूर्व खुफिया एवं सुरक्षा अधिकारी यशोवर्धन आजाद की पुस्तक 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' इस यात्रा के कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाती है, जो बताते हैं कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में खेल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक गणनाएं होती रही हैं। पुस्तक में आजाद ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध, राजनीतिक हस्तक्षेप और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की है।

क्रिकेट को भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में अक्सर केवल खेल के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोनों देशों के इतिहास में क्रिकेट कई बार कूटनीति का माध्यम भी बना है और कई बार सुरक्षा तथा राजनीति की जटिलताओं का आईना भी। वर्ष 2004 का भारत का पाकिस्तान दौरा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक दशक से अधिक समय बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी। इसे 'मैत्री दौरा' कहा गया और उस समय दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें चल रही थीं। हालांकि मैदान पर दिखाई देने वाले खेल के पीछे सुरक्षा, खुफिया जानकारी और राजनीतिक निर्णयों की एक जटिल कहानी थी।

पूर्व खुफिया एवं सुरक्षा अधिकारी यशोवर्धन आजाद की पुस्तक 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' इस यात्रा के कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाती है, जो बताते हैं कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में खेल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रणनीतिक गणनाएं होती रही हैं। पुस्तक में आजाद ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध, राजनीतिक हस्तक्षेप और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की है।

वर्ष 2004 के पाकिस्तान दौरे से जुड़ा एक प्रसंग विशेष रूप से ध्यान खींचता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ कराची में एक टेस्ट मैच आयोजित करना चाहते थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा व्यवस्था ने कराची और पेशावर को टेस्ट मैच के लिए उपयुक्त नहीं माना था। आजाद उस समय भारतीय टीम की सुरक्षा से जुड़े दल में थे। सुरक्षा आकलन के बाद कराची और पेशावर में टेस्ट मैच नहीं कराने की सलाह दी गई थी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर को टेस्ट मैचों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया।

इसी बीच आजाद को तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का फोन आया। आडवाणी ने उनसे पूछा कि क्या कराची में टेस्ट मैच कराने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आजाद ने सुरक्षा संबंधी कारणों की जानकारी दी। इसके बाद उनसे कहा गया कि वे इस मामले को खुफिया ब्यूरो के निदेशक के सामने उठाएं। आडवाणी स्वयं भी इस संबंध में खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात करने वाले थे।

आजाद के अनुसार, उन्हें यह जानकारी भी आश्चर्य हुआ कि यह आग्रह सीधे उपप्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा। बाद में उन्हें विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान संबंधी जिम्मेदारी संचाल रहे अधिकारी अरुण सिंह से पता चला कि यह स्वयं राष्ट्रपति मुशर्रफ़ का अनुरोध था। लेकिन अंततः सुरक्षा सलाह को प्राथमिकता दी गई और सुरक्षा दल द्वारा सुझाए गए कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया।

यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन दिखाई देता है। एक ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की इच्छा थी और दूसरी ओर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का पेशेवर आकलन। राजनीतिक नेतृत्व के सामने विकल्प था कि वह कूटनीतिक अवसर को प्राथमिकता दे या सुरक्षा संबंधी सलाह को। अंततः सुरक्षा आकलन को स्वीकार करना यह बताता है कि संवेदनशील मामलों में राजनीतिक नेतृत्व और पेशेवर सुरक्षा तंत्र के बीच संवाद तो जरूरी है, लेकिन निर्णय लेते समय सुरक्षा संबंधी



तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

2004 का पाकिस्तान दौरा सामान्य क्रिकेट दौरा भी नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध लंबे समय से राजनीतिक तनाव की छाया में रहे थे। ऐसे समय में भारतीय टीम का पाकिस्तान जाना दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की बड़ी कोशिश के रूप में देखा गया। मैदान पर खिलाड़ी थे, दर्शकों में उत्साह था और राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह संबंध सुधारने का अवसर था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए वही दौरा अत्यंत संवेदनशील अभियान था।

आजाद ने कराची में होने वाले एकदिवसीय मैच से पहले पैदा हुई सुरक्षा चिंताओं का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, भारतीय टीम को आतंकवादी खतरे की सूचना मिली थी। इसी दौरान 11 मार्च 2004 को स्पेन के मैड्रिड में रेलगाड़ियों में बम विस्फोट हुए, जिनमें 193 लोगों की मौत हुई और करीब दो हजार लोग घायल हुए। उस समय पाकिस्तान के कबायली और शहरी क्षेत्रों में अल-कायदा के शीर्ष कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बारे में भी खुफिया जानकारी थी।

भारतीय टीम की सुरक्षा व्यवस्था संचाल रहे आजाद के सामने चुनौती केवल खतरे को पहचानने की नहीं थी, बल्कि यह तय करने की भी थी कि खिलाड़ियों को कितनी जानकारी दी जाए। उन्होंने टीम के प्रबंधक आर. एस. शेठ्टी और प्रशिक्षक जॉन राइट के साथ इस सूचना को साझा किया और तत्काल इसे सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया। अगले दिन भारतीय टीम को कराची में एकदिवसीय मैच खेलना था।

इसके बाद इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारतीय टीम को आतंकवादी खतरे की सूचना मिली। यह सूचना खुफिया स्रोत से प्राप्त हुई थी और उसमें विशेष रूप से कराची तथा भारतीय टीम का उल्लेख था। हालांकि खतरे का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था, फिर भी इसे गंभीरता से लिया गया। टीम का सामान पहले ही तैयार

करवा दिया गया, ताकि मैच समाप्त होते ही भारतीय टीम सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो सके।

यह प्रसंग बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था केवल हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का नाम नहीं है। इसमें यात्रा की समय-सारणी, खिलाड़ियों की गतिविधियां, सामान की आवाजाही, आने-जाने के रास्ते, संभावित खतरे और आपात स्थिति में तत्काल निकासी की योजना तक शामिल होती है। किसी संवेदनशील देश में राष्ट्रीय टीम का दौरा अपने आप में एक जटिल सुरक्षा अभियान बन जाता है। इस गंभीर वातावरण के बीच आजाद की पुस्तक में सचिन तेंदुलकर से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग भी है। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर तेंदुलकर ने काले सूट और काले ब्रीफकेस लिए खड़े सुरक्षाकर्मियों की ओर संकेत करते हुए मासूमियत से पूछा कि क्या वे हथप्रमाण बटनहू लेकर खड़े हैं। जब आजाद ने उन्हें जैमर के बारे में बताया तो तेंदुलकर ने उससे जुड़े कई सवाल किए। यह प्रसंग सुरक्षा के गंभीर संसार के बीच एक मानवीय और हल्का क्षण सामने लाता है। लेकिन 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' की महत्ता केवल ऐसे रोचक प्रसंगों में नहीं है। पुस्तक की वास्तविक उपयोगिता इस बात में है कि लेखक ने सत्ता, पुलिस और सुरक्षा तंत्र को भीतर से देखा है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप से निपटने वाली संस्थाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आज पहले से अधिक जटिल हो गया है। आतंकवाद के साथ-साथ साइबर अपराध, संगठित अपराध, सीमा पार से आने वाले खतरे और सूचना के दुरुपयोग जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे समय में सुरक्षा संस्थाओं की पेशेवर क्षमता के साथ उनकी जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

2004 का कराची टेस्ट प्रसंग इसी संस्थागत विवेक का

उदाहरण है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की इच्छा थी, भारत के राजनीतिक नेतृत्व के सामने कूटनीतिक अवसर था, लेकिन सुरक्षा आकलन ने जोखिम की ओर संकेत किया। अंततः टेस्ट मैच के कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया। उस समय यह निर्णय शायद केवल क्रिकेट कार्यक्रम से जुड़ा मामला लगा हो, लेकिन वर्षों बाद सामने आए विवरण इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण बना देते हैं।

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्रिकेट की भूमिका हमेशा दोहरी रही है। यह कभी जनता को जोड़ने का माध्यम बना, तो कभी दोनों देशों के तनाव का प्रतीक। 2004 का दौरा उस दौर की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता था जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश हो रही थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने एकदिवसीय श्रृंखला 3-2 से ओर टेस्ट श्रृंखला 2-1 से जीती। लेकिन स्कोरबोर्ड से परे इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुरक्षा और कूटनीति की थी।

आजाद की पुस्तक का व्यापक संदेश भी यही है कि गणतंत्र की सुरक्षा केवल पुलिस या खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए मजबूत संस्थाएं, पेशेवर निर्णय, राजनीतिक संयम, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों के प्रति सम्मान आवश्यक है। सुरक्षा तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखते हुए उसकी लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है।

इस दृष्टि से 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' केवल एक पूर्व अधिकारी का संस्मरण नहीं है। यह उस व्यवस्था के भीतर झांकने का अवसर देती है, जहां सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले निर्णयों के पीछे अनेक स्तरों पर विचार और जोखिम का आकलन चलता है। कराची का वह टेस्ट मैच अंततः नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे की कहानी अब सामने आई है।

क्रिकेट के मैदान पर मैच होते हैं, श्रृंखलाएं जीती और हारी जाती हैं और रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौर की सफलता केवल खेल परिणामों से तय नहीं होती। उसके पीछे कूटनीति, खुफिया जानकारी, सुरक्षा आकलन और राजनीतिक निर्णय भी काम करते हैं।

2004 का पाकिस्तान दौरा इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी कोई मैच इसलिए भी इतिहास का हिस्सा बन जाता है क्योंकि वह खेला नहीं गया। कराची में टेस्ट मैच न कराने का फैसला उस समय शायद एक प्रशासनिक निर्णय था, लेकिन आज वह भारत-पाकिस्तान संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के बीच जटिल संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है।

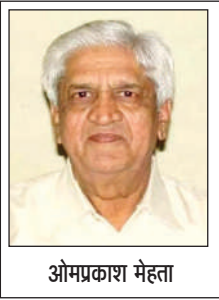
यशोवर्धन आजाद की 'पॉलिसिंग द रिपब्लिक' ऐसे ही पढ़ें के पीछे के संसार को सामने लाती है। इसका महत्व क्रिकेट से आगे जाकर उस प्रश्न में है कि लोकतांत्रिक गणराज्य अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है और संकट के समय राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षा संस्थाएं किस तरह निर्णय लेती हैं। यही इस पुस्तक को समकालीन भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक दस्तावेज बनाता है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

महंगी चीनी, आयात क्यों?

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, निर्यातक और खपत वाला देश है। उससे आगे ब्राजील ही है। एक अच्छे साल और अच्छी फसल के मद्देनजर भारत औसतन 70 लाख टन चीनी निर्यात करता रहा है, लेकिन 280-285 लाख टन की घरेलू खपत को सुनिश्चित करने के बाद ही निर्यात किया जाता है। इस साल भी तमाम स्थितियों के बाद 41 लाख टन से अधिक चीनी 'अतिरिक्त भंडारण' में है, फिर भी बीते गुरुवार, 20 अगस्त, को 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति सरकार ने दी है। बेशक यह चीनी शुल्क-मुक्त होगी। आयात की यह नौबत 10 साल के बाद आई है। मोदी सरकार ने 30 सितंबर, 2026 तक सभी तरह की चीनी के निर्यात पर पाबंदी थोप रखी है। दरअसल मई के बाद जब चीनी मिलों के बड़े व्यापारी और एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, तो उन्होंने दावा किया था कि इस साल 343.5 लाख टन चीनी का उत्पादन संभव है, लिहाजा निर्यात खोल दिया जाए। सरकार ने उनके आंकड़ों पर भरोसा किया और निर्यात खोल दिया, लेकिन जब हकीकत खुलने लगी, तो उत्पादन 279 लाख टन पर आकर ठहर गया, जबकि देश में चीनी की खपत 280-285 लाख टन आंकी गई है। नतीजा यह हुआ कि जो चीनी 21 जुलाई को करीब 45 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वह 31 जुलाई को उछल कर 50 रुपए हो गई और बीते शुक्रवार, 21 अगस्त, को 65 रुपए चीनी का भाव हो गया। एक ही महीने में चीनी 20 रुपए महंगीहू। स्थितियों को भांपते हुए बड़े व्यापारियों, थोक विक्रेता, थोक के औद्योगिक उपभोक्ताओं ने जुलाई से पहले ही चीनी की जमाखोरी शुरू कर दी, ताकि त्योहारों के मौसम में अधिक दामों पर चीनी बेचकर मुनाफ़ कमाए जा सके। अगस्त में कड़े चीनी मिलों ने बिक्री ही रोक दी। वे भी मुनाफ़ाखोरी, कालाबाजारी की जमात में खड़ी हो गईं। अब 20 अक्तूबर को दशहरा है और 8 नवंबर को दिवाली है। भारत के दोनों ही राष्ट्रीय त्योहार हैं, लेकिन उनसे पहले ही चीनी की मिठास 'कड़वी' हो गई है। एथेनॉल को 'खलनायक' बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हालांकि हम ई-20 नीति के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि भारत सरकार तमाम पारदर्शी जवाब नहीं दे पाई है। ई-20 का देश में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। नवंबर, 2025 से जुलाई, 2026 के दौरान तेल कंपनियों को 810.67 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई किया गया है। उसमें से 259.24 करोड़ लीटर, अर्थात 32 फीसदी, गन्ने से तैयार किया गया है, जबकि शेष 68 फीसदी एथेनॉल मक्का, शीरे, भारतीय खाद्य निगम के चावल और टूटे या सड़े-खराब अनाज से बनाया गया है। पहले 34 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए तय किया जाना था, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण 30 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने को मुहैया कराई गई। उसके बावजूद भंडारों में चीनी उपलब्ध थी। तो सवाल है कि चीनी का आयात क्यों किया जा रहा है? चीनी खुदरा बाजार में महंगी क्यों होती जा रही है? क्या जमाखोरों, मुनाफ़ाखोरों, बिचौलिया ताकतों और वर्चस्ववादी मिलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये ह्कालाबाजारीहू बार-बार उभर कर सामने आते हैं? इस खेल में बेचारा किसान तो गायब है। खरबों किसानों को न तो खाद्य-संकट मानते हैं और न ही यह राष्ट्रीय अराजकता का कारण बन सकती है। अलबत्ता मिलकालीन खडगे और अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेता 'राजनीति' जरूर करेंगे। बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में गन्ने की फसल, बीते साल सितंबर-अक्तूबर में, अधिक बारिश से प्रभावित हुई थी। नतीजतन उत्पादन कम हुआ और भंडारण 9 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस साल भी जून में बहुत कम बारिश हुई। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। मॉनसून भी असंतुलित रहा।



ओमप्रकाश मेहता

आज यदि सबसे अधिक दुःखी आत्मा होगी तो वह राष्ट्रभक्त बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय की होगी, जिनकी अनुपम कृति ह्यवन्दे मातरम् पर राजनीति हावी हो गई है। खासकर इस राष्ट्रीय गीत



मनोज कुमार अग्रवाल

नाबालिग बच्चों में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है। छोटी उम्र के बच्चों में आक्रामकता, चोरी, मारपीट और यहाँ तक कि गंभीर हिंसक अपराधों जैसे हत्या लूट के रझान में इजाफा देखा जा रहा है। इसके मुख्य कारणों में हिंसक डिजिटल कंटेंट, पारिवारिक संवाद की कमी और गलत संगत शामिल हैं। हालांकि हमें तैलंगाना के नालगोंडा में एक महिला प्रिंसिपल की उनके ही स्कूल के तरुण छात्र ने एक अन्य साथी छात्र के साथ मिलकर लूटपाट कर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने 48 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझा लिया है और दो छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर पैसों और आलीशान जीवन शैली के लिए अपराध की योजना बनाई थी।यह वारदात समाज में नाबालिग बच्चों में अपराध की दुनिया के प्रति बढ़ता आकर्षण कानून और समाज से बेखौफ उन्मुक्त और अय्याशी भरे जीवन शैली को जीने की ललक को बताती है। भारत में क्राइम के मामलों को लेकर एनसीआरबी ने चीकाने वाली रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक, हत्या, रेप और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता बढ़ी है। दिल्ली में 40 फीसदी से भी अधिक ऐसे केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि तैलंगाना के कोंडमल्लेपल्ली स्थित नागार्जुन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर कल्लू रूपा रेड्डी 12 अगस्त की सुबह अपने घर में

के छंदों को लेकर जंग छिड़ी है, पिछले नौ दशक से इसके दो ही छंद गाए जाते रहे हैं, जबकि इसके कुल मिलाकर आठ छंद हैं, अब देश के गृहमंत्री ने इसी को राजनीतिक विवाद की मुख्य बना दिया है तथा इसी आधार पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। गृहमंत्री का कहना है कि काँग्रेस मुस्लिम तृष्टिकरण के कारण फिर पुरानी गलती को दोहरा रही है। वास्तव में इस विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के दिन उस समय हुई जब दिल्ली स्थित काँग्रेस मुख्यालय में ध्वज वंदन के समय सोनिया गांधी एक कार्यकर्ता को कोई निर्देश दे रही थी, आरोप है कि सोनिया ने राष्ट्रगान का अपमान किया और वे राष्ट्रभक्ति पसंद नहीं करती। यद्यपि आज तक प्रमुख सत्ताधारी दल भाजपा के भी किसी ध्वज वंदन

चुनौती बन रहा है नाबालिगों का अपराध की ओर बढ़ता रझान

मृत पाई गई। उनके शरीर पर चाकू के 27 घाव थे। उनका शव तब बरामद हुआ जब उनके पति, जो हैदराबाद में थे, ने पड़ोसियों को बताया कि वह उनके फोन का जवाब नहीं दे रही हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने उन्हें मृत पाया। इसके बाद पुलिस ने पांच टीमें बनाई और सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य, फिंगरप्रिंट, तकनीकी डेटा और संदिग्धों की गतिविधियों की जांच की और 80 से अधिक लोगों से पूछताछ की। बाबू शब्द के कारण छात्रों ने जांचकर्ताओं को तब सुराग मिला जब उन्हें पता चला कि फोन बंद होने से पहले रूपा रेड्डी ने अपनी चाची से बात करते समय बाबू शब्द का इस्तेमाल किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शरथ चंद्र पवार के अनुसार उसकी बातचीत के दौरान रिकॉर्ड किया गया आखिरी शब्द बाबू था। हमने इस बात की जांच की कि वह किसका जिन्न कर रही थी, और इससे हमें स्कूल के छात्रों की ओर संकेत मिला। इसके बाद जांचकर्ताओं ने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और कक्षा 10 के उन पांच छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो स्कूल से अनुपस्थित रहे थे। उन्हें पता चला कि उनमें से दो छात्र पिछले कुछ दिनों में खूब पैसा खर्च कर रहे थे और पार्टियां दे रहे थे।पवार ने बताया कि दोनों छात्रों को बुधवार सुबह हॉस्टल में लिया गया और पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने योजना के अनुसार रूपा रेड्डी की हत्या की थी। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपियों को इससे पहले रूपा रेड्डी द्वारा फटकार लगाई गई थी, जब उनके छात्रावास के बैग से नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था।इसने उनके माता-पिता को सूचित किया, और उन्हें छात्रावास से निकालकर दैनिक छात्र का दर्जा दे दिया गया।पुलिस को संदेह है कि इससे प्रधानाचार्य के प्रति असंतोष पैदा होने में योगदान हो सकता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के इस दौर में ऑनलाइन गेम और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध असीमित और हिंसक सामग्री बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर डाल रही है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अपराध के

कार्यक्रम में 'वन्दे मातरम्' का पूरा गान गाते नही देखा गया, पिछले नौ दशकों से इसके प्रारंभिक दो छंद ही गाते देखा गया है, किंतु यह राजनीति की बलिहारी है, जिसने इसे राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना दिया और अब इस मुद्दे पर भाजपा-काँग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। सत्तारूढ़ दल, काँग्रेस के इस फैसले को आत्मघाती बता रहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस गान को 1937 में 'राष्ट्रीय गान' का दर्जा दिया गया था। इसीलिए इसे आजादी के पहले की धरोहर मानकर पूरा राष्ट्र इसका सम्मान करता है और बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में झण्डा वंदन की सलामी के समय इसे गाया जाता रहा है, किंतु अब जक इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है तो इस गान के भविष्य को लेकर पूरा देश चिंतित है।

लगभग हर क्षेत्र में नाबालिग शामिल पाए गए। इसमें कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं। जिसमें रेप, हत्या और किडनैपिंग मे मामलों में 12 साल से कम उम्र तक के नाबालिग भी शामिल रहे। इस साल जनवरी को 2016 में राजधानी दिल्ली में तीन नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तीनों पर एक 6 साल की बच्ची का रेप करने का आरोप था. कानूनन तीनों नाबालिग थे लेकिन तीनों ने मिलकर इतनी हैवानियत की थी कि वह बच्ची ठीक से चल भी नहीं पा रही थी. इसी तरह अप्रैल में नागपुर में पुलिस ने 13 नाबालिगों को पकड़ा था. इन सभी ने मिलकर एक 22 साल के व्यक्ति की बेहमी से हत्या कर दी थी. हत्या 100 रुपये के विवाद को लेकर हुई थी. आए दिन गंभीर अपराधों में नाबालिग अपचाारियों की बढ़ती भागीदारी समाजशास्त्र और बाद मनोविज्ञान के अध्येताओं के लिए चुनौती बन रही है। ये घटनाएं इतना बताने के लिए काफी हैं कि हमारे देश में अब नाबालिग तेजी से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं. हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है. इसमें सामने आया है कि दो साल में नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामलों में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में नाबालिगों के खिलाफ 30,555 मामले दर्ज किए गए थे. 2024 में यह बढ़कर 34,878 हो गए। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में दर्ज मामलों 58.9 लाख मामले दर्ज किए गए थे. 2023 की तुलना में यह 6 फीसदी की गिरावट थी. लेकिन इसके उलट, नाबालिगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है. चिंता वाली बात यह है कि नाबालिग रेप, मर्डर, लूटपाट और किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराधों की शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के 2,557 मामलों में नाबालिगों को आरोपी बनाया गया था. इसके अलावा मर्डर और किडनैपिंग जैसे 8,943 मामलों में आरोपी नाबालिग थे. 2024 में नाबालिगों के खिलाफ रेप के 1,067 और मर्डर के 1,120 मामले दर्ज किए गए थे.

अब इस विवादित राजनीति का असर कहां-कहां तक होता है, यह फिलहाल कल्पना से परे है, क्योंकि पूरे देश की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में इसका पूरे सम्मान के साथ गाय किया जाता है। अब फिलहाल यह भी मानना मुश्किल है कि इस विवाद के पीछे भी 'वोट बैंक' की राजनीति छुपी है, क्योंकि देश के दो विशेष वर्ग मुस्लिम और ईसाई आरोपित है कि इस गान का सम्मान नहीं करते? अब जो भी हो किंतु सबसे अहम बिन्दु यही है कि इस अहम् राष्ट्र भक्ति से जुड़े बिन्दु को राजनीति का अंग बनाना किसी भी स्थिति में ठीक नही कहा जा सकता। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दरअसल माता-पिता का बच्चों के साथ संवाद कम होना, घरेलू हिंसा या परिवार का विघटन बच्चों को विद्रोही बना रहा है। पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में हर समय जीतने का भारी तनाव बच्चों में गुस्सा और कूट पैदा कर रहा है।खुरी संगत और सहपाठियों (पीयर प्रेशर) के दबाव में आकर बच्चे जल्दी गलत रास्ते पर कदम रख देते हैं।विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव है कि गरीबी कम करके और शहरी वातावरण को बेहतर करके नाबालिगों को हिंसा में आने से रोका जा सकता है. अमरी और गरीबी का अंतर अपराध को बढ़ाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपनी भड़ास निकालने के लिए हिंसा सबसे आसान जरिया बन जाती है. इसलिए गैर-बराबरी कम करने के साथ-साथ स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के बच्चों की हिंसा और अपराध से बचाया जा सकता है.इसके साथ ही माता-पिता बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें। बच्चों द्वारा देखे जाने वाले डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करें। घर और स्कूल में ऐसा वातावरण दें जहाँ बच्चा खुलकर अपनी बात रख सके।जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि उनकी काउंसलिंग कर उन्हें सुधारने को हिंसा से सहानुभूति भरे कानून का नाबालिग अपचारी दुरुपयोग न करें इस ओर भी निगरानी जरूरी है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) भारतीय पशुधन के लिए रोग मुक्त भविष्य

बिहान भारत

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई। यह भारत के सबसे बड़े पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य देशव्यापी टीकाकरण और निगरानी के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) तथा ब्रूसेल्लिस पर नियंत्रण और इनका उन्मूलन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एफएमडी के 147.16 करोड़ टीके लगाए गए जिसका लाभ 8.04 करोड़ किसानों को मिला है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि से रोगों के मामले घटाने में काफी मदद मिली है। 2019 में एफएमडी के 132 मामले सामने आए थे जिनकी संख्या 2025 में घट कर 40 हो गई। इसी तरह, ब्रूसेल्लिस के मामले भी 2019 में 22 से घट कर 2025 में 15 हो गए। एनएसपी एंटीबाँडी की मौजूदगी भी 2019 में 20.8 प्रतिशत से घट कर 2025 में 8.1 प्रतिशत रह गई है। इससे साक्ष्य आधारित निगरानी और रोग नियंत्रण की निरंतर कोशिशों के परिणामस्वरूप एफएमडी के प्रसार में कमी आने का संकेत मिलता है। देश में पिछले 3 वर्षों में सीरोटाइप एशिया-1 से उत्पन्न एफएमडी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस कार्यक्रम को मजबूत पशु चिकित्सा अवसंरचना, पशुधन के बारे में डिजिटल आंकड़ों, अनुसंधान संस्थानों और वन हेल्थ पहलकदमियों से सहायता मिली है। भारत पशुधन पोर्टल पर 39.00 करोड़ से अधिक मवेशी पंजीकृत हैं। 14019 सचल पशु चिकित्सा इकाइयों ने 136 लाख किसानों को उनके घर पर सेवा मुहैया कराते हुए 276 लाख मवेशियों का इलाज किया है। एनएडीसीपी रोग नियंत्रण, डिजिटल निगरानी और महामारी की तैयारी को समर्थित करते हुए भारत में रोगों से सुरक्षित पशुधन क्षेत्र में योगदान कर रहा है।

रोग मुक्त पशुधन क्षेत्र का निर्माण

पशुधन लंबे समय से ग्रामीण भारत में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या 535.78 करोड़ है जिनमें 302.79 करोड़ गोवंशीय मवेशी हैं। पशुधन की यह बड़ी संख्या पशु स्वास्थ्य और आरोग्य के महत्व को रेखांकित करती है। एफएमडी और ब्रूसेल्लिस जैसे संक्रामक रोगों ने ऐतिहासिक तौर पर दूध उत्पादन में कमी, प्रजनन में विफलता और व्यापार प्रतिबंधों के कारण काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अत्यंत संक्रामक वायरल रोग एफएमडी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है। इस रोग से पशु की दूध उत्पादन, विकास, प्रजनन और कार्य क्षमता में गिरावट आती है। एफएमडी का प्रभावी नियंत्रण सभी संवेदनशील पशुओं के नियमित सामूहिक टीकाकरण पर निर्भर करता है। ब्रूसेला एबॉर्टस बैक्टीरिया से होने वाला ब्रूसेल्लिस गायों और भैंसों का प्रजनन संबंधी रोग है। यह मुख्यतः पशुओं के प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। इससे उनके सामान्य प्रजनन कार्य बाधित होते हैं। यह प्रजनन और दूध देने की क्षमता को बाधित करता है जिससे दुग्ध और मांस उत्पादन प्रभावित होता है। मवेशियों के इस रोग का कोई उपचार नहीं होने की वजह से टीकाकरण ही सबसे प्रभावी और संवहनीय उपाय है। सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देशव्यापी टीकाकरण और निगरानी के माध्यम से एफएमडी तथा ब्रूसेल्लिस पर नियंत्रण और इनका उन्मूलन है। इसका लक्ष्य एफएमडी से बचाव के लिए सभी पशुओं का साल में 2 बार 100 प्रतिशत टीकाकरण है। इसके अंतर्गत 4 से 8 माह की बछियों का ब्रूसेल्लिस से बचाव के लिए उनके जीवनकाल में एक बार टीकाकरण किया जाता है।

एनएडीसीपी के अंतर्गत समेकित कार्रवाई के जरिए पशुधन रोगों में कटौती

इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी योग्य पशुओं के साल में 2 बार टीकाकरण

से एफएमडी और 4 से 8 महीने की बछियों को जीवनकाल में एक दफा टीका लगा कर ब्रूसेल्लिस को नियंत्रित करना है। यह रोग की निगरानी और शीत श्रृंखला (कोल्ड चैन) लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था में भी मदद करता है। प्रभावित होने के अंदेश वाली सभी गायों और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एफएमडी के खिलाफ हर 6 महीनों पर सामूहिक टीकाकरण। कार्यक्रम के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के उद्देश्य से सार्वजनिक जागरूकता और अधिकारियों के लिए अनुकूलन अभियान। कान टैंगिंग, पंजीकरण और भारत पशुधन पोर्टल पर पशु के संबंध में जानकारीयों की अपलोडिंग। टीकाकरण के पूर्व और पश्चात नमूना परीक्षण के जरिए सीरो-निगरानी। गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए टीकों और शीत श्रृंखला उपकरणों की खरीद। महामारी का निरीक्षण, वायरस पृथक्कीकरण और उसकी किस्म का निर्धारण तथा क्वारंटाइन और जांच चौकियों के माध्यम से पशुओं की आवाजाही का नियमन। लगातार आंकड़ा सृजन, निगरानी और प्रभाव आकलन। टीकाकरण कर्मियों को लगाए गए प्रति टीके पर कम-से-कम 3 रुपए की दर से आर्थिक लाभ।

सीरो-निगरानी और सीरो-निरीक्षण

सीरो-निगरानी में रोग की आशंका और प्रतिरोधक क्षमता का अनुमान लगाने के लिए आबादी के स्तर पर एंटीबाँडी की उपस्थिति का आकलन शामिल है। दूसरी ओर, सीरो-निरीक्षण में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझने के लिए एंटीबाँडी स्तरों की दीर्घकालिक ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

मवेशियों के स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता

एनएडीसीपी की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने एक अधिक व्यापक और संवहनीय पशु स्वास्थ्य फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (एलएचडीसीपी) के तहत रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत किया है। संशोधित एलएचडीसीपी के तहत, पशुधन स्वास्थ्य उपायों के एकीकृत कार्यान्वयन और प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए एनएडीसीपी, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचडीसीपी) घटक तथा 'पशु औषधि' पहल को एक ही व्यापक योजना में शामिल कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) का कुल बजट परिव्यय 2,010 करोड़ रुपये है।

एफएमडी और ब्रूसेल्लिस के नियंत्रण में राष्ट्रीय प्रयास और परिणाम

देशभर में निरंतर टीकाकरण, निगरानी और मॉनिटरिंग के प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों का पैमाना और हासिल हुए मापने योग्य परिणाम निम्नानुसार हैं:

खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी)

एनएडीसीपी के तहत अब तक कुल 147.16 करोड़ एफएमडी वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं, जिससे 8.04 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जानवरों में एफएमडी के जोखिम को कम करना वर्ष 2024 से चरवाहों की भेड़ों और बकरियों के लिए भी एफएमडी टीकाकरण शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जानवरों के झुंड शामिल हैं, इसका उद्देश्य बीमारी को फैलने से रोकना है।

प्रतिरक्षा में सुधार और बीमारी के प्रकोप में गिरावट

टीकाकरण के बाद एंटीबाँडी प्रतिक्रिया

का आकलन करने के लिए किए गए सेरो-मॉनिटरिंग (रक्त-परीक्षण निगरानी) से पता चलता है कि खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) वायरस के सेरोटाइप ओ, ए और एशिया 1 के खिलाफ औसत सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा क्रमशः 78.1%, 71.7% और 77.6% है। ये स्तर मजबूत सामूहिक प्रतिरक्षा को दर्शाते हैं। इस बेहतर हुई प्रतिरक्षा के कारण बीमारी के मामलों में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट किए गए एफएमडी के मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 132 से घटकर 2025 तक केवल 40 रह गई है। यह देशव्यापी टीकाकरण कवरेज की प्रभावशीलता को दर्शाता है। एफएमडी टाइप ओ: भारत और दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम और व्यापक रूप से पाया जाने वाला सेरोटाइप। इसके कारण बार-बार रोग होता है। एफएमडी टाइप ए: एक अत्यधिक परिवर्तनशील सेरोटाइप, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से बदलता है और इसके लिए सही तरह से मेल खाने वाले टीकों की जरूरत होती है। एफएमडी टाइप एशिया 1: मुख्य रूप से भारत सहित दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला एक सेरोटाइप, लेकिन टाइप ओ के मुकाबले यह कम फैला हुआ है।

ब्रूसेल्लिस

एनएडीसीपी के तहत, 4-8 महीने की आयु की गायों की बछियों को जीवन में एक बार ब्रूसेल्लिस की खुराक दी जाती है।

प्रतिरक्षा में सुधार और बीमारी में गिरावट

वर्ष 2025 में, टीकाकरण के बाद की निगरानी से पता चलता है कि गायों की बछियों में सेरोकनवर्जन दर (टीका लगाए गए जानवरों का वह प्रतिशत जिनमें एंटीबाँडी विकसित होती है) 75.63% और भैंस की बछियों में 67.17% दर्ज की गई। ये निष्कर्ष प्रभावी प्रतिरक्षा को दर्शाते हैं, जिससे ब्रूसेल्लिस के मामलों में भारी कमी आई है। रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 2019 में 22 से घटकर 2025 में 15 रह गई, जो कार्यक्रम के तहत किए गए प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

गोवंशीय मवेशियों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में सुधार

देशी और मिश्रित नस्ल के मवेशियों की उत्पादकता: देशी (स्थानीय) और मिश्रित नस्ल के मवेशियों की उत्पादकता 2014-15 में प्रति मवेशी प्रति वर्ष 927 किलोग्राम से बढ़कर 2024-25 में 1,343.2 किलोग्राम हो गई है, जो 44.89% की वृद्धि को दर्शाता है। भैंस की उत्पादकता: इसी तरह, इसी अवधि के दौरान भैंसों की उत्पादकता प्रति जानवर प्रति वर्ष 1,880 किलोग्राम से बढ़कर 2,365.2 किलोग्राम हो गई है, जो 25.80% की वृद्धि है। गोवंशीय मवेशियों की उत्पादकता: नतीजतन, भारत में गोवंशीय मवेशियों की औसत उत्पादकता 2014-15 में प्रति जानवर प्रति वर्ष 1,640 किलोग्राम से बढ़कर 2024-25 में 2,250 किलोग्राम हो गई है। यह 36.63% की वृद्धि है और दुनिया भर में किसी भी देश द्वारा दर्ज की गई उत्पादकता में सबसे अधिक वृद्धि है। दूध उत्पादन में वृद्धि: भारत का दूध उत्पादन 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 247.87 मिलियन टन हो गया है। यह पिछले दशक में 69.4% की वृद्धि को दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों की उत्पादकता को और बढ़ाना और 2030 तक प्रति जानवर प्रति वर्ष 3,000 किलोग्राम का औसत दूध

उत्पादन हासिल करना है।

बीमारी की रोकथाम के लिए संस्थागत और अवसंरचना से जुड़ी सहायता प्रणालियाँ अनुसंधान और निगरानी में सहायता

एफएमडी (खुरपका-मुंहपका रोग) और ब्रूसेल्लिस नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्रमुख आईसीएआर संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के अंतर्गत वैक्सीन अनुसंधान, गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी, सेरो-सरवैलेंस (रक्त-परीक्षण निगरानी), बीमारी की मॉडलिंग और राज्यवार नमूना संग्रह (सैंपलिंग) शामिल हैं। ये उपाय कार्यक्रम का प्रभावी और विज्ञान-आधारित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ केंद्रित टीका खरीद

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण संबंधी सामान खरीदने और कोल्ड-चेन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एचआईडीएफ) के माध्यम से अलग अलग उद्यमियों, निजी कंपनियों और अन्य पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता पशु चिकित्सा टीकों और दवाओं की मेन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना में मदद करती है।

पशु चिकित्सा अवसंरचना और सेवा वितरण

प्रत्येक पशुपालक तक पशु स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) को मजबूत किया जा रहा है। 129 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,019 एमवीयू संचालित हैं। ये टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं। अब तक, इस पहल से 136 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 276 लाख पशुओं का इलाज किया गया है।

भारत पशुधन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल एकीकरण

भारत पशुधन पोर्टल पशुधन पंजीकरण, एफएमडी और ब्रूसेल्लिस टीकाकरण डेटा को एक जगह लाता है, जिसमें प्रत्येक पशु को 12 अंकों की एक विशिष्ट टैग आईडी आवंटित की जाती है। जुलाई 2026 तक, पोर्टल पर 39.00 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके थे। इसने वास्तविक निगरानी,

बेहतर ट्रैस करने की क्षमता और पशुधन विकास कार्यक्रमों के अधिक पारदर्शी तथा डेटा-

आधारित कार्यान्वयन को सक्षम बनाया है। भविष्य में एआई-सक्षम एनालिटिक्स, टीकाकरण ट्रेसबिलिटी, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और साक्ष्य-आधारित योजना बीमारी की निगरानी तथा संसाधनों के आवंटन को और मजबूत कर सकती हैं।

जागरूकता और किसानों की भागीदारी

ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गभार्धान तकनीशियन (एमएआईटीआरआई) के माध्यम से किसानों तक पहुंचने की कोशिशों को मजबूत किया गया है, जो घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। अब तक, वित्तीय सहायता के माध्यम से 39,810 तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन

'वन हेल्थ' दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य की आंतरिक परस्पर निर्भरता को स्वीकार करता है। जानवरों की बीमारियों का जल्दी पता लगाने, निगरानी और नियंत्रण को मजबूत कर-के, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जूनोटिक रोगों (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों) के प्रसार के जोखिम को कम करने में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, यह रोगाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है तथा माहुरी समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारी और क्षमता को मजबूत करता है। 7 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 21वाँ बैठक में, प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने अंतर-मंत्रालयी प्रयासों के साथ एक ह्यराष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के स्थापना को मंजूरी दी। यह मिशन देश में मौजूदा सभी 'वन हेल्थ' गतिविधियों को समन्वित, समर्थित और एकीकृत करने तथा जहां भी उपयुक्त हो, कमियों को दूर करने का कार्य करेगा। एनडीडीबी का ब्रूसेल्लिस नियंत्रण मॉडल टीकाकरण, सुरक्षित अपशिष्ट निपटान, मजबूत जैव-सुरक्षा, जन जागरूकता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर जोर देकर इसे और मजबूत करता है; विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मनुष्यों में ब्रूसेल्लिस का अक्सर पता ही नहीं चल पाता है। 'वन हेल्थ' बढ़ती बीमारियों के खतरे और तेजी से बदलते पर्यावरण के बीच लोगों, जानवरों और इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए एक व्यावहारिक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। महामारी की तैयारी के लिए पशु स्वास्थ्य

सुरक्षा को मजबूत करना: महामारी कोष परियोजना 2024 में, सरकार ने महामारी की तैयारी और उससे निपटने के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी कोष परियोजना की शुरुआत की। यह जी20 महामारी कोष के सहयोग से चलाई जा रही 25 मिलियन अमरीकी डालर की एक परियोजना है। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक, खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व बैंक की सझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना महामारी की तैयारी में सुधार के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करके एनएडीसीपी का पूरक बनती है। यह जीनोमिक और पर्यावरणीय निगरानी सहित रोग निगरानी को बेहतर बनाती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रयोगशाला अवसंरचना का उन्नयन करती है और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देती है। इन उपायों से जूनोटिक और सीमा पार पशु रोगों का जल्द पता लगाने और समय पर उसका इलाज करने में सुधार होता है। इस पहल के तहत, सरकार ने भारत में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए: मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (एसवीटीजी)¹: एक व्यापक रूपरेखा जो वैज्ञानिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं के तकसंगत उपयोग और रोगाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) प्रबंधन को बढ़ावा देती है। यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एमआर) पर राष्ट्रीय कार्य योजना का भी समर्थन करता है। पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी)²: बीमारी के प्रकोप के दौरान तैयारियों को मजबूत करने और तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की है। यह समय पर रोग के रोकथाम और प्रभावी ढंग से उबरने के उपायों में मदद करती है। ये दस्तावेज पशु चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करेंगे। ये पशु स्वास्थ्य संकटों के प्रति समय पर और

प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेंगे और बीमारी के प्रबंधन से जुड़े प्रोटोकॉल को भी मजबूत करेंगे।

भारत के पशुधन संपदा की सुरक्षा

एनएडीसीपी भारत के सबसे व्यापक और डेटा-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक बनकर उभरा है। निरंतर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण, मजबूत निगरानी प्रणालियों, डिजिटल एकीकरण और लक्षित वित्तीय तथा ढांचागत सहायता के माध्यम से, इस कार्यक्रम ने एफएमडी और ब्रूसेल्लिस में मापने योग्य कमी दर्ज की है। बीमारियों के प्रकोप में तेज गिरावट, रेवड़ प्रतिरक्षा में सुधार और गोवंशीय उत्पादकता में स्पष्ट लाभ यह दर्शाते हैं कि बीमारी पर नियंत्रण सीधे तौर पर किसानों के लिए आर्थिक, पोषण संबंधी और आजीविका लाभों में परिवर्तित हो रहा है। पशु रोगों की बीमारियों का जल्द पता चलने से संक्रमण के फैलने का खतरा कम होता है, एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रीवर्डशिप मजबूत होती है और भविष्य की जूनोटिक महामारियों के खिलाफ राष्ट्रीय तैयारी बेहतर होती है। भविष्य की प्राथमिकताओं में एफएमडी-मुक्त स्थिति के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाना, प्रयोगशाला मान्यता का विस्तार, जीनोमिक निगरानी, एआई-सक्षम बीमारी इंटेलिजेंस, जलवायु-अनुकूल निगरानी प्रणालियाँ और मजबूत 'वन हेल्थ' जैसे प्रयास शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े पशुधन टीकाकरण अभियान से लेकर डिजिटल रूप से सक्षम रोग निगरानी तंत्र तक, एनएडीसीपी ने एक स्वस्थ, अधिक उत्पादक और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पशुधन क्षेत्र बनाने की नींव रखी है। जैसे-जैसे भारत हृदयकसित भारत 2047 के ओर बढ़ रहा है, पशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश खाद्य सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और महामारी से निपटने की क्षमता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम बना रहेगा।



दिल्ली में स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में स्वाइन फ्लू और वेक्टर जनित बीमारियों की मौजूदा स्थिति और रोकथाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों, अस्पतालों की तैयारियों, निगरानी व्यवस्था और संभावित मामलों को लेकर विभागीय तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में खास तौर पर स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की स्थिति पर नजर रखने और इनके प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने के साथ-साथ आने वाले दिनों में बीमारियों की रोकथाम के लिए फील्ड स्तर पर निगरानी और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को और मजबूत करने को लेकर भी दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

दिल्ली में मानसून के दौरान वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने को देखते हुए सरकार की ओर से इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इससे पहले सफ़दरजंग अस्पताल ने अपने एक बयान में कहा कि अस्पताल स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया कि मरीज की जरूरत और मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से इलाज किया जाता है, साथ ही अस्पताल मामलों पर नजर रखता है और जरूरी इंतजाम बनाए रखता है। बता दें हाल के हफ्तों में दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्ली में एच1एन1 के 1,777 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि राजधानी में इन्फ्लूएंजा-ए के भी 2,300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं।

महाराष्ट्र में रिक्शा चला रहे हजारों युवकों को आजीविका से वंचित करना उचित नहीं

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए परिवहन मंत्री से अपील की है कि रैपिडो, ओला और उबेर के चलते राज्य में हजारों की संख्या में रिक्शा चला रहे मराठी युवकों को आजीविका से वंचित करना उचित नहीं है। राउत ने पत्र में लिखा- महोदय, राज्य के कुछ मंत्रियों के रैपिडो कंपनी के साथ वित्तीय और व्यावसायिक संबंध हैं। रैपिडो ने अब तक दहाई हांडी, गणेशोत्सव और कुछ मंत्रियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है और करोड़ों रुपए दिए हैं। कुछ मंत्रियों को चुनाव के लिए भी धनराशि दी है। इसलिए ऐसा लगता है कि हजारों रिक्शा चालकों को इनके नाम पर फंसाकर एहसान चुकाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने आगे लिखा- जब महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री का मूल पेशा ही रिक्शा चालक है, तो इस राज्य के रिक्शा चालकों की आजीविका छीनना उचित नहीं है। मैं इस मुद्दे पर रिक्शा चालक संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ आपसे मिलना चाहता हूं। उचित समय और स्थान की जानकारी दें। कृपया मुझे सूचित करें। हाल ही में संजय राउत ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। 20 अगस्त को संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने और मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम कार्यालय के उद्घाटन पर चिंता व्यक्त की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत की ओर से लिखे गए पत्र को प्रति सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार को भी भेजी गई थी। राउत ने शहरी सहकारी बैंकिंग परिसंपत्तियों से संबंधित मंत्रालय के हालिया फैसलों पर आपत्तियां रखी थीं। राउत ने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर पत्र मराठी में लिखा है ताकि जनता समझ सके कि उनके शब्दों में, महाराष्ट्र के शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के साथ किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया था और पनयूसीएफडीसी के जरिए महाराष्ट्र और गोवा के शीर्ष शहरी सहकारी बैंक की संपत्ति को उसके सदस्यों की सहमति के बिना जब्त कर लिया गया था। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन पर सीधा हमला बताया था।

बारिश का कहर : सोनभद्र में कनहर बांध के फाटक खुले, हिमाचल में 125 सड़कें बंद

सोनभद्र (एजेंसी)। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया है। सोनभद्र जिले में कनहर सिंचाई परियोजना के केनमेंट एरिया में लगातार वर्षा के चलते अगवार स्थित कनहर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी बारिश और भूस्खलन की चपेट में है, जहां 125 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर 262.350 मीटर पर पहुंचने के बाद, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई विभाग ने तत्परता दिखाकर बांध के छह फाटक (संख्या 2, 4, 5, 6, 11 और 13) खोल दिए हैं। फाटकों के खुलने से कनहर नदी के डाउनस्ट्रीम में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है और नदी उपनाद पर है। प्रशासन ने तटीय और डूब क्षेत्रों में आम लोगों तथा मेवेशियों के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

तमिलनाडु में 1.30 करोड़ परिवारों को मिलेंगे सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर

-विजय सरकार ने ‘अन्नपूर्णा सुपर 6’ योजना का किया ऐलान

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में ‘अन्नपूर्णा सुपर 6’ योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत राज्य की महिला परिवार मुखियाओं को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना की शुरुआत आगामी जनवरी में पोंगल पर्व से होगी। सरकार ने इसके लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये सालाना बजटीय प्रावधान करने की बात कही है। योजना से 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विजय के मुताबिक योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के बाद उसकी कीमत सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए वापस की जाएगी। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की आधिकारिक बिलिंग को आधार बनाया जाएगा।

2.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वालों को लाभ

‘अन्नपूर्णा सुपर 6’ योजना का लाभ उन



परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई और कीमतों में वृद्धि से पिछले चार महीनों में परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इसके चलते कई परिवार वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने को मजबूर हुए। सरकार का उद्देश्य एलपीजी पर होने वाले खर्च की भरपाई कर परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना है।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ेगा

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा और आवागमन से जुड़ी ‘वेट्रो पयानम’ योजना के विस्तार की भी घोषणा की। इसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा बढ़ाई जाएगी। योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। इसके तहत महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस और डीलक्स सरकारी बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री मुफ्त यात्रा कर

सकेंगे। जिलों के बीच आवागमन के लिए मुफ्सिल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराया वाली बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार के अनुसार ‘वेट्रो पयानम’ के क्रियान्वयन पर करीब 6,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होने का अनुमान है। इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं होगी और मुफ्त यात्राओं की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने ‘वेट्रो विजन डॉक्यूमेंट’ के तहत महिला सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और आजीविका को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान किए जाने की जानकारी दी। इनमें ‘सिंगा पेन’ स्पेशल टास्क फोर्स, ‘थैमामन श्रंगामोशिरम’, ‘वेट्रो मगलिर आडुगल वलरमु’ और ‘अन्नानिन सीर’ जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।

क्लोरीन गैस लीक होने से 40 लोग प्रभावित, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत

-सभी को अस्पताल में कराया भर्ती, 5 गंभीर को आईसीयू में किया शिफ्ट

नागपुर, एजेंसी। नागपुर में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के गोधनी इलाके में सोमवार को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। गोधनी नगर पंचायत द्वारा संचालित

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव की घटना के बाद करीब 40 लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रभावित लोगों में संयंत्र के 8 से 10 कर्मचारी और आसपास रहने वाले 20 से 25 लोग शामिल हैं। गैस रिसाव के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में रखा है। वहीं, अन्य मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनपर नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। गैस के प्रभाव को नियंत्रित करने के साथ ही आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर नजदीकी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

अमरावती के सरकारी अस्पताल में आग, वेंटिलेटर फटा 3 शिशुओं की मौत

अमरावती, एजेंसी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित एक सरकारी अस्पताल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में आग लगने से कम से कम तीन नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जिंदगी की शुरुआत करने वाले इन नवजात शिशुओं ने अभी अपनी मां को जीभर कर देखा भी नहीं होगा कि इस दर्दनाक हादसे ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि यह आग नियोनेटल यूनिट में एक वेंटिलेटर में विस्फोट होने के कारण लगी। यह भयावह घटना बुधवार तड़के करीब 3-30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार, नियोनेटल यूनिट में एक वेंटिलेटर में हुए धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और पूरे वार्ड में धुआं भर गया। उस समय यूनिट में कुल 39 नवजात शिशु भर्ती थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वार्ड को खाली करवाना शुरू कर दिया। इस दौरान छह नवजातों को गंभीर हालत में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया



गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, तीन नवजातों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। आग इतनी भीषण थी कि एनआईसीयू वार्ड की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वार्ड में मौजूद बेड, मशीनों और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए, बिस्तर राख के ढेर में बदल गए। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने पूरी कोशिश की कि बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन हुए की वजह से तीन मामूलों को

नहीं बचाया जा सका।घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने इस पूरे मामले की हादसे जांच के आदेश दे दिए हैं। यह पता चला है कि आग लगने का जिम्मेदार कौन है और अस्पताल में आग बुझाने के लिए क्या इंतजाम थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संसद का सत्रावसान अब तक क्यों नहीं? कांग्रेस ने उठाए सवाल

-जयराम बोले- क्या परिसीमन बिल के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं अमित शाह?

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद अब तक कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आशंका जताते हुए सवाल किया है, कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब भी परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आमतौर पर लोकसभा की कार्यवाही

अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और सत्रावसान के बीच दो से चार दिन का अंतर होता है। हालांकि कई मौकों पर दोनों प्रक्रियाएं एक ही दिन भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्रावसान को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

2015 और 2021 का उदाहरण दिया कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2015 के मानसून सत्र में स्थगन और सत्रावसान के बीच 28 दिन तथा 2021 में 20 दिन का अंतर रहा था। हालांकि, उनका दावा है कि उन मौकों पर मौजूदा जैसी परिस्थितियां नहीं थीं। उन्होंने सवाल किया कि इस बार इतनी असाधारण देरी क्यों हो रही है। ऐसे में जयराम रमेश ने पूछा कि क्या सरकार किसी विशेष सत्र के जरिए परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी कर

रही है और इसके लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में संसद की कार्यप्रणाली और नियमों पर आधारित एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर की पुस्तक ‘प्रीक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ का एक पृष्ठ भी साझा किया है।

राष्ट्रपति के आदेश से होता है सत्रावसान

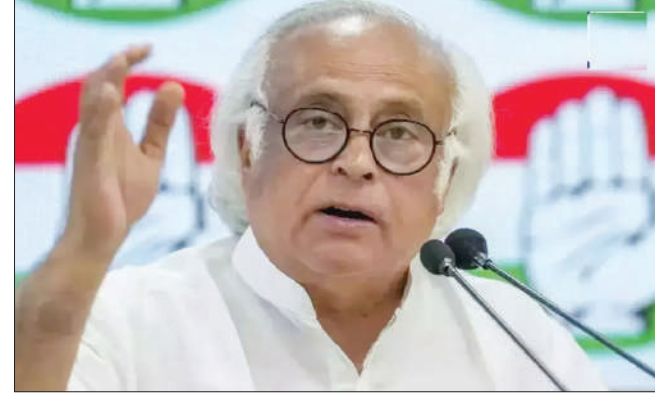
किताब के हवाले से कांग्रेस नेता ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से संसद के सत्र की औपचारिक समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है। राष्ट्रपति इस संबंध में प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। आमतौर पर सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सत्रावसान किया जाता है, हालांकि यह पहले भी हो सकता है।

कांग्रेस ने 543 सीटें स्थिर रखने की मांग की

कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 वर्षों तक स्थिर रखने की मांग दोहराई है। पार्टी का कहना है कि इसी मौजूदा संख्या पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए और इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने भी महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के अपने संकल्प को दोहराया है।

अप्रैल में विधेयक नहीं जुटा पाया था दो-तिहाई बहुमत

कांग्रेस के अनुसार, 17 अप्रैल को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत



हासिल नहीं कर सका था। मत विभाजन में शामिल 528 सांसदों में 298 ने विधेयक के पक्ष और 230 ने विरोध में मतदान किया। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद जयराम रमेश

मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में भगदड़, छह श्रद्धालु घायल, सावन के आखिरी सोमवार को हुआ हादसा

पटना (एजेंसी)। मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर धाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर बड़ा हादसा होते-होते बचा। मंदिर में दर्शन और जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मुख्य द्वार पर भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम छह श्रद्धालु घायल हो गए। यह घटना सोमवार सुबह लगभग 6-25 से 7 बजे के बीच उस समय हुई जब भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। घायलों को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ का दबाव बढ़ा, कुछ लोगों ने नियंत्रण खो दिया और अफरा-तफरी मच गई। स्थिति भगदड़ में बदल गई, और इस दौरान कुछ श्रद्धालु नीचे गिर गए। भीड़ के दबाव में दबने से कई लोगों को चोट आई।

सूचना के अनुसार, इस घटना में चार महिलाएं और दो पुरुष समेत कुल आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। मौके पर पहले से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। स्थिति बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। स्थानीय संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस का सहयोग किया और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद की। उन्होंने गिरे हुए लोगों को उठाया और घायल श्रद्धालुओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालकर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। सावन की अंतिम सोमवारी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुरखे इंतजाम किए गए थे और स्वयं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भी मंदिर की व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए थे। हालांकि, सुबह अचानक मुख्य गेट पर भीड़ का अत्यधिक दबाव बढ़ जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति को जल्द ही संभाल लिया गया और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया।

पेपर लीक रोकने के लिए बिहार सरकार ने बनाई समिति



कैलेंडर के निर्माण, प्रश्न पत्रों में सुधार, परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने और पेपर लीक की रोकथाम के प्रभावी उपायों को लागू करना शामिल है। सरकार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।

पाकिस्तानी गैंगस्टर की सक्रियता ने पंजाब में बढ़ाई टेंशन

-शहजाद भट्टी निशाने पर, हार्ड अलर्ट जारी

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब में एक बड़ी आतंकवादी घटना की साजिश रचे जाने की गंभीर आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों की नौद उड़ा दी है। खुफिया एजेंसियों द्वारा राज्य में हार्ड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इस खतरनाक योजना के तहत, दो महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी भी की जा चुकी है, जिसने सुरक्षा प्रतिष्ठानों में खलबली मचा दी है। हालांकि, इन आशंकाओं को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खुफिया इनपुट की गंभीरता को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा

व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी गुर्गों विशेष रूप से अमृतसर जिले में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला करने की फिराक में हैं। यह संवेदनशील जानकारी पंजाब पुलिस सहित देश की अन्य सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की गई है। एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस इनपुट को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और तत्काल प्रभाव से सभी संवेदनशील स्थानों, विशेषकर सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाए। इस अलर्ट के बाद, सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है और सदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुलासे के तहत, इन दो सदिग्ध ऑपरेटिव्स की पहचान राणा भाई और मलिक के रूप में हुई है। खुफिया इनपुट के हवाले से बताया गया है कि साजिश के तहत अमृतसर के खासा खवनी

और बेस के पास स्थित बूढ़ा ठेह की विस्तृत रेकी की गई है। यह बात और भी चिंताजनक है कि खासा खवनी में कुछ समय पहले ही एक रहस्यमय धमाका हुआ था, हालांकि उस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और विस्फोट खवनी की बार्ड्री चॉल के पास हुआ था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि उस धमाके के तार भी किसी पूर्व नियोजित साजिश से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अब तक पिछली घटना और मौजूदा इनपुट्स के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका है। सुरक्षा एजेंसियां इन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ भारत में पहले से ही व्यापक कार्रवाई चल रही है। यह गिरोह धार्मिक और संवेदनशील स्थानों पर हमला करने, साथ ही राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की साजिशों में शामिल रहा है।

संक्षिप्त डायरी

**पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप में स्कूल, हॉस्पिटल, थाने
समेत होंगी ये खास सुविधाएं, सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट**



पटना (एजेंसी) पाटलिपुत्र सैटेलाइट डाउनशिप को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इसमें लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, उद्योग समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। पूरे 130 सेक्टरों में पाटलिपुत्र सैटेलाइट डाउनशिप को बसाया जाएगा। पटना से आशुतोष दीक्षित की रिपोर्ट पटना के आसपास एक ऐसा नया शहरी क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है, जहां घरों के साथ स्कूल, अस्पताल, बाजार, उद्योग, मनोरंजन और सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं एक साथ होंगी। 81,654.12 एकड़ में बनने वाला पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट डाउनशिप 130 सेक्टरों में विकसित होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी विस्तृत कार्य योजना सार्वजनिक कर दी है। विभाग का लक्ष्य 2037 तक 10 लाख लोगों को यहां बसाने का है। डाउनशिप में सबसे अधिक 28,723.95 एकड़ जमीन आवासीय क्षेत्र के लिए रखी गई है। 17,616.13 एकड़ जमीन शहरी कृषि क्षेत्र के लिए सुरक्षित की गई है। 8,652.03 एकड़ में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी। 4,651.67 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। पाटलिपुत्र डाउनशिप में क्या-क्या होगा? हर 10 लाख की आबादी के हिसाब से अस्पताल डाउनशिप की योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। 10 लाख की आबादी के मानक के अनुसार यहां 66 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 पॉली क्लिनिक, 4 जनरल हॉस्पिटल और 10 वेटरनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। 400 प्री-प्राइमरी स्कूल और 200 प्राइमरी स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में संस्थान होंगे। यहां 400 प्री-प्राइमरी, 200 प्राइमरी और 130 सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा आठ कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी भी होगा। सुरक्षा के लिए 11 थाने, 22 पुलिस चौकियां इसके साथ ही बड़ी आबादी के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी का पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। डाउनशिप में 22 पुलिस चौकियां, 11 थाने, एक बटालियन हेडक्वार्टर और पांच फायर स्टेशन बनाने की योजना है। मेट्रो से जुड़ेगी डाउनशिप सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो को डाउनशिप तक लाने की योजना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए भी अलग से जमीन सुरक्षित की गई है। खास बात यह है कि डाउनशिप में सबसे अधिक 28,723.95 एकड़ जमीन आवासीय क्षेत्र के लिए तय की गई है।

पटना (पूजेसी) बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को पहले की ही तरह 4 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स प्र पोस्ट शेयर किया. इस में उन्होंने साफ़ किया कि इस योजना को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए. बिहार के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले लोन को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड केलियर कर दिया है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले की ही तरह 4 लाख रुपये तक का लोन विद्यार्थियों को दिया जाएगा. इसे लेकर खुद सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी. सम्राट चौधरी ने एक्स प्र क्या



लिखा? सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना के संबंध में

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए. उच्च

शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और यह सुविधा

आगे भी पूर्ववत् ही जारी रहेगी।' सीएम के पोस्ट से विद्यार्थियों को राहत आगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी लिखा, 'बिहार सरकार युवाओं की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'

शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।' इस तरह से अब तक विद्यार्थियों के बीच उनके उच्च शिक्षा को लेकर कम लोन मिलने की जो चिंता थी, वह कहीं ना कहीं दूर हुई। 19 अगस्त को जारी हुआ था आदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 19 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था।

उस आदेश की माने तो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये तक की मदद विद्यार्थियों को मिलने की बात कही गई थी. इस आदेश के बाद उन गरीब छात्रों की चिंता बढ़ गई थी, जिन्हें

महंगे कोर्स के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से सोमवार को एक पोस्ट शेयर कर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। नीतीश कुमार के सीएम रहते शुरू हुई थी योजना जानकारी के मुताबिक, यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना के तहत 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, ताकि 12वीं पास बच्चों को आगे की पढ़ाई यानी कि उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक परेशानी न हो। इसके तहत विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक की सहायता की जाती है। फिलहाल बिहार में उच्च शिक्षा में नामांकन दर (GER) केवल 17.1 प्रतिशत है, जबकि देश का औसत 28.4 प्रतिशत है। राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक पहुंचाना चाहती है।

कपड़े की रस्सी से बंधा मिला NEET छात्र और उसकी मां का शव, चंदवारा घाट से बरामद

पटना (एजेंसी) मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी से नीट की तैयारी कर रहे एक 17 वर्षीय छात्र उसकों मां का शव बरामद हुआ है। दोनों के श्व कपड़े की रस्सी से बंधे मिले थे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित चंदवारा घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी से सोमवार को 35 वर्षीय महिला पिंकी देवी और उसके 17 वर्षीय बेटे आशर्श रीशन का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गयी है। दोनों के श्व कपड़े की रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। मृतकों की पहचान सीतामढ़ी जिले के मूल निवासी मां-बेटे के रूप में हुई है। बेटा नदी की तैयारी कर रहा था और अपनी



मां के साथ मुजफ्फरपुर में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा

था. स्कूटी लावारिस मिलने पर
शुरू हुई तलाश बताया गया कि

रविवार शाम दोनों स्कूटी से घर से निकले थे. देर रात तक वापस नहीं

लट्टे पर परिजनों ने उनकी तलाशी शुरू की। इसी दौरान चंदवारा घाटा पुलिस के पास बूढ़ी गंडक नदी के बांधों में पर उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसडीआरएफ शरत कुमार पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और नदी व आसपास के इलाके में देर रात तक खोजबीन की। एसडीआरएफ की टीम ने नदी से निकाले गए एक बुधवार को एसडीआरएफ की मदद से नदी में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें मां-बेटे के शव बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, दोनों के हाथ कपड़े की रस्सी से बंधे मिले हैं। हालांकि, आसपास के लोगों ने नहीं देखा था, जिससे मामले को

लेकर कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं. पुलिस खंगाल रही है कॉल डिटेल और साक्ष्य पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. महिला के मकान मालिक और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, हालांकि उसकी परेशानी की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाल रही है. शव मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और आत्महत्या, हादसा संभवित रूप से संभावनाओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है

**उपेंद्र कुशवाहा का आया बयान, तेजस्वी भी समर्थन में;
पटना के आंदोलनकारी छात्र सड़क पर उतरने को तैयार**

पटना (एजेंसी) शिक्षक बहाली के लिए पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन के बाद आंदोलन को बल मिला है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 25 अगस्त को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक बहाली में रक्तियाँ बढ़ाने, परीक्षा को सिंगल शिफ्ट में, आयोजित करने व नेगेटिव मार्किंग हटाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद आंदोलन में नई हलचल देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने छात्रों के हित में बयान देते हुए कहा कि सरकार को आंदोलनकारी छात्रों से सीधे



बातचीत करनी चाहिए. इस बयान का स्वागत करते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि इतने बड़े नेता का समर्थन मिलने से सरकार से उम्मीद जग रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारा आंदोलन सही दिशा में



आगे बढ़ रहा है। जदयू नेताओं से समर्थन की अपील दिलीप कुमार ने सत्ताधारी दल जनता दल (यूनाइटेड) के शीर्ष नेतृत्व से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने संजय झा, ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और

निशांत कुमार से आग्रह किया कि वे भी घरना स्थल पर आएँ और छात्रों के जायज आंदोलन को अपना समर्थन दें, इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनकारा अभ्यर्थियों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएँ और एकजुटता बनाए रखें, छात्रों में बंटी राय, 25 को बड़े प्रदर्शन की तैयारी, कुशवाहा के बयान के बाद घरना स्थल पर मौजूद छात्रों को मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, कुछ छात्रों का कहना था कि सरकार से बातचीत की उम्मीद बंधी है, जबकि कई अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीते 18 सालों से केवल आश्वासन ही मिल रहा है और अब सरकार से भरोसा उठ चुका है, इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी आंदोलन को समर्थन मिल चुका है, छात्रों ने

स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो 25 तारीख को सड़क-अभ्यर्थी जोरदार विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतरेंगे। हालांकि इसपर एक राय नहीं है। पहले बिहार भर में फैले, फिर पटना में निकलेंगे छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि छात्र-युवाओं के हित में 25 अगस्त के प्रदर्शन को उनका नैतिक समर्थन है। लेकिन उन्होंने सरकार को दो दिन का समय दिया है। अगर दो दिन में मांगें नहीं मानी गईं तब वे बिहार बंद का ऐलान कर सकते हैं। उनका कहना है कि पहले बिहार के अन्य जिलों में प्रदर्शन फैले, फिर वो पटना में सड़क पर उतरेंगे। उन्हें अंदेशा है कि अगर वो अभी सड़क पर उतरें तो सरकार उन्हें पकड़कर जेल भेज देगी और आंदोलन खत्म हो जाएगा।

पटना-बरख्तियारपुर रेलखंड पर हादसा: पटना-दुमका एक्सप्रेस की चपेट में आने से वैशाली की महिला की मौत

पटना (एजेंसी) खुसरूपर स्टेशन के पास एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि, मृतक के पति ने चलती ट्रेन से गिरने की आशंका जताई है। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। पटना-बखियापुर रेलखंड पर खुसरूपर स्टेशन के पास सोमवार सुबह करीब 9 बजे 55 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी। हादसा पूर्वी रेल मण्डल के हास रेल पोल संख्या 512/22 के समीप हुआ। मृतका की पहचान वैशाली जिले के शिवनगर निवासी उषा देवी, पति वीरचंद्र राय ऊर्फ बीरा राय के रूप में हुई है। पटना-दुमका एक्सप्रेस की चपेट में आने की सूचना जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह डाउन लाइन में रेल पोल संख्या 512/22 के पास महिला के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली। बताया गया कि 13334 डाउन पटना दुमका एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला की मौत पर ही मौत हो गयी। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गयी। सूचना मिलने पर जीआरपी की टीम मौके पहुंची।



जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जीआरपी पोस्ट प्रभारी राजीव कंत शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ भेज दिया गया. पति के आवेदन से बदला मामले का एंगल घटना की जांच के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया, जब मुक्ता के पति वीरचंद्र राय ने जीआरपी को लिखित आवेदन दिया. आवेदन में उन्होंने आशंका जतायी कि उषा देवी रहने दैक

पाए करते समय ट्रेन की चोपट में नहीं
 आयीं, बल्कि संभव है कि वह चलती
 चोपट से गिर गयी हों। पुलिस वालों
 पहलुओं की कर रही गुप्त परिजन की
 और से जतायी गयी आशंका के बाद
 पुलिस अब पूरे मामले की जांच दोनों
 पहलुओं से कर रही है, महिला ट्रेन की
 चोपट में कैसे आयीं और घटना के
 समय वह रेल ट्रेक के पास कैसे पहुंचीं,
 इसका पता लगाने का प्रयास किया जा
 रहा है, जोआरपी का कहना है कि जांच
 के बाद ही घटना की वास्तविक वजह
 स्पष्ट हो सकेगी, फिलहाल शव का
 पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

पटना एयरपोर्ट पर सात दिन में दूसरी घटना, लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के विमान से टकरायी पक्षी, 164 यात्री बाल-बाल बचे

पटना (एगेंसी) दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान पक्षी से टकरा गई। सौभाग्य से, सभी 164 यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन प्लाइट में देरी हुई। यह पटना एयरपोर्ट पर एक सप्ताह में दूसरी एसी घटना है। दिल्ली से 164 यात्रियों को लेकर पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 1 सोमावार सुबह लैंडिंग के दौरान पक्षी से टकरा गयी. घटना के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर एहतियातन इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया गया और फायर एवं अन्य आपात सेवाओं को तैनात किया गया. हालांकि विमान ने सुबह 7.43 बजे सुरक्षित लैंडिंग की. दाहिने इंजन के पास टकरायी पक्षी, कोई नुकसान नहीं एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, नएवी की



ओर बढ़ते समय विमान के पायलट ने दाहिने इंजन के पास पक्षी के टकराने की आशंका जतायी थी. लैंडिंग के बाद विमान

की जांच की गयी, जिसमें पक्षी के टकराने की पुष्टि हुई, लेकिन इंजन को किसी तरह का नुकसान नहीं मिला. जरूरी जांच पूरी होने के

बाद विमान को दिल्ली लौटने के लिए फिट घोषित कर दिया गया. दिल्ली लौटने वाली फ्लाइट 79 मिनट देर से उड़ी 1 के दिल्ली

लौटेने वाली फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे. यह विमान निर्धारित समय सुबह 8.45 बजे के बजाय 10.09 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ. इस वजह से उड़ान 79 मिनट विलंबित रही. इस फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले राजद सांसद मनोज झा ने अपनी यात्रा दोपहर की एयर इंडिया फ्लाइट से करेने का फैसला किया. पटना एयरपोर्ट पर एक सप्ताह में दूसरी बार बर्ड हिट पटना एयरपोर्ट पर एक सप्ताह के भीतर एयर इंडिया के विमान के साथ पक्षी टकराने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली-पटना एयर इंडिया की फ्लाइट से पक्षी टकराया था. उस घटना के बाद विमान को दो दिनों के लिए सेवा से हटाया पड़ा था. विमान की मरम्मत के लिए दिल्ली से मेंटेनेंस

इंजीनियरों की टीम बुलायी गयी थी. जॉच और मरमतल के बाद डोजीसाँप की अनुमति से विमान को दोबारा परिचालन के लिए मंजूरी मिली थी. रनवे पर मिला 1.5 किलो का चमगादड़ का शव एयरपोर्ट के आसपास बढ़ रही पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं की गतिविधियों को लेकर भी चिन्ता बढी है. रविवाक को उड़ान परिचालन शुरू होने से पहले नियमित निरीक्षण के दौरान रनवे पर करीब 1.5 किलो वजन के चमगादड़ का शव मिला था. अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले की शाम किसी विमान ने पक्षी से टकराने की सूचना नहीं दी थी. वारिश के मौसम में बढ़ता है पक्षियों का खतरा अधिकारियों के अनुसार, मानसून के दौरान रनवे के आसपास तेजी से घास बढ़ने

के कारण पक्षियों की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। घास की कटाई के दौरान जमीन से कीड़े-मकौड़े बाहर निकलते हैं, जिससे मकौड़े आकर्षित होते हैं। इससे विमानों के लिए बर्द हिट का खतरा बढ़ जाता है। एयरपोर्ट पर चेचर्स की तैनाती पक्षियों को रनवे और अपरेशनल क्षेत्र से दूर रखने के लिए एयरपोर्ट एंथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से चेचर्स की तैनाती की गयी है। ये कर्मी फायरक्रैकर्स और अन्य उपायों के जरिए पक्षियों को भगाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट के आसपास फुलतियोरिजल क्षेत्र में मौजूद मांस की दुकानों से भी पक्षियों के आकर्षित होने का खतरा बना रहता है। वन्यजीवों से खतरे को रोकने के लिए नियम नागरिक

उड़्डान की नियमावली के तहत एयरपोर्ट पर वाइरड्रगला फैजर्ट हैजर्ट जैमजैमट प्लान लालू कृषा जात है. इसके तहत पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं से विमान को होने वाले खतरों की पहचान कर उसे काम करने के उपाय किये जाते हैं. इसमें पक्षी भगाने वाले उपकरण, चूहे नियंत्रण, घास व कीट प्रबंधन, जैविक और रासायनिक नियंत्रण के साथ जागरूकता और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे उपाय शामिल हैं. पटना एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में बड़ी पक्षी टकराने की घटनाओं को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार किया. एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी से भी इस संबंध में प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी.

सोने के भाव में तेजी, चांदी की कीमत फिसली

सोना 1,132 रुपए तेज होकर 1,63,570, चांदी 1,000 रुपए गिरकर 2,45,597 एर



नई दिल्ली ।

सोना अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की अप्रत्याशित बायबैक की घोषणा के बाद सोने की कीमतों में वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में तेजी दर्ज की गई है। इस कदम ने निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की ओर बढ़ा दिया है, जबकि चांदी के भावों में सुस्ती का रुख देखने को मिला। वै श्विक बाजार में सोना 4,700 डॉलर प्रति औंस के करीब, जबकि चांदी 69 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 386 रुपये की गिरावट के साथ 1,62,052 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 1,62,438 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 1,132 रुपये की तेजी के साथ 1,63,570 रुपये के भाग,व पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 1,63,585 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 1,62,001 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,45,597 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 2,46,597 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 461 रुपये की गिरावट के साथ 2,46,136 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 2,46,475 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 2,44,815 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। चांदी के वायदा भाव ने इस साल 4,20,048 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के वायदा भाव तेजी और चांदी के नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉमेक्स पर सोना 4,673.40 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 4,680.60 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 25.70 डॉलर की तेजी के साथ 4,706.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 5,586.20 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 69.34 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला बंद भाव 69.53 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 0.37 डॉलर की गिरावट के साथ 69.16 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके भाव ने इस साल 121.79 डॉलर का उच्चतम स्तर छू लिया।

होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स का शेयर बाजार में मिला-जुला असर

नई दिल्ली ।

ब्लैकस्टोन समर्थित होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को शेयर बाजार में मिला-जुला डेब्यू किया। कंपनी का निर्गम मूल्य 60 रुपये प्रति शेयर था, जिसके मुकाबले बीएसई पर शेयर 0.58 प्रतिशत टूटकर 59.65 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जबकि एनएसई पर इसने 0.41 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 60.25 रुपये पर शुरुआत की। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 16,873.63 करोड़ रुपये रहा।

2,600 करोड़ रुपये के इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह बोली के अंतिम दिन 1.45 गुना अभिधान मिला था। कंपनी ने अपने शेयर के लिए 57-60 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था। आईपीओ से पहले, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स ने एंकर निवेशकों से 1,168 करोड़ रुपये जुटाए थे। आईपीओ की राशि मुख्य रूप से कर्ज चुकाने में प्रयोग होगा।

होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास, स्वामित्व और संचालन का काम करती है। यह 10 शहरों में करीब छह करोड़ वर्ग फुट के 46 परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है।

अमेरिका-भारत के शेयर महंगे, यूरोप में ज्यादा आकर्षक एफसीएफ यील्ड- रिपोर्ट

यूरोपीय इक्विटी भारतीय-अमेरिकी बाजारों से अधिक आकर्षक, निवेशक अब ‘वैल्यू’ बाजारों पर केंद्रित

नई दिल्ली।

एक ताजा वैश्विक रणनीति रिपोर्ट में कहा है कि जैसे-जैसे मूल्यांकन बढ़ रहे हैं, अमेरिका और भारत के शेयर बाजार, फी कैश फ्लो (एफसीएफ) यील्ड के मामले में कम आकर्षक होते जा रहे हैं जबकि यूरोप जैसे वैल्यू-ओरिएंटेड मार्केट काफी ज्यादा यील्ड दे रहे हैं। फी कैश फ्लो यील्ड असल में किसी कंपनी द्वारा अपने बाजार मूल्य के मुकाबले सृजित की गई वास्तविक नकदी

का प्रतिशत में मापने का पैमाना होता है। चूंकि अमेरिकी बाजार महंगे लगने लगे हैं, इसलिए निवेशक दूसरे बाजारों की ओर देख रहे हैं, जहां कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और मूल्यांकन के हिसाब से अभी भी आकर्षक हैं। उनका ज्यादा ध्यान एशिया के बजाय यूरोप पर है। टेक-प्रधान एसएंडपी 500 इंडेक्स का एफसीएफ यील्ड 2.7 फीसदी है जबकि यूरोपीय इक्विटी के बड़े इंडेक्स स्टॉक्स 600 का प्रतिशत में मापने का पैमाना होता है। चूंकि अमेरिकी बाजार महंगे लगने लगे हैं, इसलिए निवेशक दूसरे बाजारों की ओर देख रहे हैं, जहां कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और मूल्यांकन के हिसाब से अभी भी आकर्षक हैं। उनका ज्यादा ध्यान एशिया के बजाय यूरोप पर है। टेक-प्रधान एसएंडपी 500 इंडेक्स का एफसीएफ यील्ड 2.7 फीसदी है जबकि यूरोपीय इक्विटी के बड़े इंडेक्स स्टॉक्स 600 का प्रतिशत में मापने का पैमाना होता है। चूंकि अमेरिकी बाजार महंगे लगने लगे हैं, इसलिए निवेशक दूसरे बाजारों की ओर देख रहे हैं, जहां कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और मूल्यांकन के हिसाब से अभी भी आकर्षक हैं। उनका ज्यादा ध्यान एशिया के बजाय यूरोप पर है। टेक-प्रधान एसएंडपी 500 इंडेक्स का एफसीएफ यील्ड 2.7 फीसदी है जबकि यूरोपीय इक्विटी के बड़े इंडेक्स स्टॉक्स 600 का

इस परियोजना के तहत गैस इन्फ्रेस्ट्रक्चर, गैस कंप्रेशन सिस्टम, कंडेनसेट और उत्पादित पानी हैंडलिंग सिस्टम, प्रोपेन रेफिजरेशन सिस्टम और अन्य संबंधित उपयोगिताएं विकसित की जाएंगी। विशेष रूप से, यह प्लांट सोर गैस को प्रोसेस करने के लिए

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

संसेक्स 171 अंक, निफ्टी 33 अंक फिसला

मुम्बई।

घरेलू शेयर बाजार सोमवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट बुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स 171 अंक नीचे आकर 77,369 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ ही 24219 पर बंद हुआ। आज सबसे अधिक गिरावट बैंकों के शेयरों में रही।

निफ्टी पीएसयू इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.93 फीसदी नीचे आया जबकि धातु क्षेत्र में तेजी रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.6 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ।

निफ्टी में शामिल 50 में से 26 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट एसएसबीआई लाइफ, अडानी पोर्टर्स, बजाज फाइनेंस समेत बजाज फिनसर्व के शेयरों में दर्ज की गई। इन शेयरों में 1-1.7 फीसदी तक की गिरावट रही। वहीं बहुत वाले शेयरों में जेएस डब्ल्यू स्टील, हिंडालको के शेयर 2 से 25 फीसदी उछले जबकि आईटी सेक्टर में एचसीए टेक और

रियल एस्टेट बिक्री बुकिंग 21 फीसदी गिरी

अप्रैल-जून तिमाही में 40,000 करोड़ के करीब; गोदरेज का शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली।

देश की 28 प्रमुख सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों की सामूहिक बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 21 प्रतिशत घटकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए रह गई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा नई आवासीय परियोजनाएं शुरू न करने के कारण यह गिरावट दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 50,900 करोड़ रुपए था। निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियों से मिले आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल बिक्री बुकिंग 39,964 करोड़ रुपए रही। हालांकि, 28 कंपनियों में से 19 ने बिक्री-बुकिंग में वृद्धि दर्ज की। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज 8,651 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग के साथ सबसे आगे रही, जो पिछले साल 7,082 करोड़ रुपए थी। वहीं, डीएलएफ लिमिटेड की बिक्री बुकिंग 11,425 करोड़ रुपए से घटकर महज 657 करोड़ रुपए रह गई, जिसका मुख्य कारण तिमाही में कोई नई परियोजना शुरू न करना रहा। बेंगलुरु स्थित प्रेस्टीज एस्टेट्स भी 12,126 करोड़ रुपए से घटकर 6,579 करोड़ रुपए पर आ गई।

लौहा और सोधा जैसी कंपनियों ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। रियल एस्टेट सलाहकारों के अनुसार, इस सामूहिक गिरावट के पीछे प्रमुख कंपनियों द्वारा नई परियोजनाएं शुरू न करना, पिछले साल का मजबूत आधार प्रभाव और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते संभावित घर खरीदारों का सतर्क रुख जैसे कारक रहे।

कनाडा-अमेरिका व्यापार वार्ता टूटी, भारत-कनाडा व्यापार समझौते को मिली नई गति

प्रधानमंत्री कार्नी ने अमेरिका पर अन्य व्यापारिक सौदों को सीमित करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली ।

अमेरिका-कनाडा व्यापार वार्ता टूटने से दोनों पड़ोसी देशों के व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों से नाराज कनाडा अब नए बाजारों की तलाश में जुट गया है, जिससे भारत के साथ उसके बहुव्रतीक्षित समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को एक नया रणनीतिक आयाम मिल गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी

ने अमेरिका पर अंतिम समय में अन्य व्यापारिक सौदे करने की कनाडा की क्षमता को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। अमेरिका से वार्ता टूटने के बाद, कनाडा ने डेढ़ अरब उपभोक्ताओं तक अपनी शुल्क-मुक्त पहुंच को अगले छह महीनों में भारत और आसियान जैसे नए समझौतों से दोगुना करने का संकल्प लिया है। वार्ता विफल होने के बाद, अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के कनाडाई वस्तु



इंफोसिस के शेयर भी 0.8 से 1.5 फीसदी बढ़े जिससे बाजार को निचले स्तरों से समर्थन मिला और इससे गिरावट रुकी रही। इसके अलावा आज विशाल मेगा मार्ट, मुथूट फाइनेंस और सीमेंस के शेयरों में भी बढ़त रही।

24 से 31 अगस्त के बीच 9 आईपीओ, निवेश से पहले जोखिम समझें

नईदिल्ली । शेयर बाजार में इस सप्ताह आईपीओ की जोरदार हलचल है। 24 से 31 अगस्त के बीच नौ कंपनियां करीब 3,500 करोड़ जुटाने के लिए बाजार में उतर रही हैं। इनमें फार्मा, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, टेक्सटाइल, प्रोजेक्ट्स और पावर सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं।

सबसे बड़ा इश्यू सिम्बायोटेक फार्मालैब का 1,757 करोड़ का है। कंपनी एपीआई, न्यूट्रिशनल और स्पेशलिटी उत्पाद बनाती है। इसकी दो-तिहाई से अधिक आय अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आती है। कंपनी के शीर्ष पांच उत्पादों से करीब 63व्न राजस्व आना निवेशकों के लिए जोखिम है। इश्यू में ₹1,607 करोड़ का हिस्सा ऑफर फॉर सेल का है, जबकि केवल 150 करोड़ नया पूंजी निवेश है।

2.स्काईवेज एयर सर्विसेज का 582.80 करोड़ का इश्यू भी निवेशकों के आकर्षण में है।

कंपनी एयर और ओशन फेट फॉरवर्डिंग का कारोबार करती है, उसकी आय का बड़ा हिस्सा एयर फ्रेट पर निर्भर है। वैश्विक व्यापार, मुद्रा दरों और अंतरराष्ट्रीय नीतियों में बदलाव से कारोबार हमेशा प्रभावित हो सकता है।

3.हाई-टेक इंजीनियर्स, मधुर निट क्राफ्ट्स, एबीएच हेल्थकेयर, अन्नू प्रोजेक्ट्स, सुमैक्स इंजीनियरिंग, ल्युमिनो इंडस्ट्रीज और क्रिक फॉरसिक सॉल्यूशंस के इश्यू भी इसी अवधि में निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं।

निवेशकों को केवल जीएमपी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए।एसएमई कंपनियों में कम कारोबार और ज्यादा उतार-चढ़ाव का जोखिम हमेशा बना रहता है। कंपनी का कर्ज, मुनाफा, प्रमोटर हिस्सेदारी, वैल्यूएशन और आईपीओ से मिलने वाली राशि को देखकर ही फैसला करना बेहतर होगा। कंपनी जिस तरीके से भारी प्रीमियम ले रहे हैं उसमें निवेशकों का जोखिम भी बढ़ा है।

आरबीआई के रियायती स्वेप से रुपया बेअसर, अरबों डॉलर भंडार में, बाजार में नहीं

आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है, जिसके जवाब में कनाडा ने भी जवाबी शुल्क लगाने की कसम खाई है। यह घटनाक्रम भारत-कनाडा सीईपीए पर बातचीत को निर्णायक बढ़त दे सकता है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य अरविंद विरमानी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन में तेजी लाने का आह्वान किया है।

वहीं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के एक अे धिकारी ने

इसे भारत के लिए चेतावनी बताया, जो अमेरिका से बातचीत कर रहा है। उन्होंने भारत को अपनी नियामक और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा और संतुलित लाभ वाली रियायतों पर जोर देने को कहा।

भारत और कनाडा ने इस साल मार्च में सीईपीए वार्ता फिर से शुरू की थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करना है।

आरबीआई के रियायती स्वेप से रुपया बेअसर, अरबों डॉलर भंडार में, बाजार में नहीं

2013 के विपरीत इस बार डॉलर बाजार में जारी नहीं हुई, मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रियायती स्वेप योजनाओं के तहत भारत में अरबों डॉलर का प्रवाह हुआ है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका रूपये की विनिमय दर पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 21 अगस्त तक आए कुल 72.85 अरब डॉलर से अधिक की यह विदेशी मुद्रा सीधे केंद्रीय बैंक के भंडार में जमा हो गई है, बजाय इसके कि यह हाजिर बाजार में रुपये को मजबूती देती। यह स्थिति 2013 की समान योजना से बिल्कुल विपरीत है, जब रुपये में महत्वपूर्ण मजबूती देखी गई थी। आरबीआई ने 8 जून को रियायती स्वेप योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत, बैंक विदेशी मुद्रा अनिवार्य-बैंक (एफसीएनआर-बी) जमाओं के माध्यम से जुटाए गए डॉलर को रिजर्व बैंक के पास जमा कर रुपये प्राप्त करते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था में रुपये की नकदी तो बढ़ी है, लेकिन विदेशी मुद्रा सीधे आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में जुड़ गई है। परिणामस्वरूप, रुपये की विनिमय

क ऑफ बढ़ावा दे एक अे धिकारी ने कहा कि बाजार में विदेशी मुद्रा तभी आ सकती है, जब रिजर्व बैंक हाजिर बाजार में हस्तक्षेप कर डॉलर जारी करे या अपनी फॉरवर्ड पोजिशन घटाए। ऐसा न होने के कारण, बाजार पूर्ववत् व्यवहार कर रहा है और वैश्विक कारकों के मुताबिक मुद्रा बाजार को प्रभावित कर रहा है।

अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट , ईरान पर सख्ती से पहले कच्चे तेल में गिरावट

निवेशकों ने की मुनाफावसूली, ब्रेट कूड 1.3 और डब्ल्यूटीआई 1.6 फीसदी गिरा

नई दिल्ली ।

ईरान पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा से पहले सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने पिछले सप्ताह की तेजी के बाद मुनाफावसूली की, वहीं अमेरिका द्वारा ईरान के आर्थिक संबंधों को निशाना बनाने की तैयारी ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी। शुरुआती कारोबार में ब्रेट कूड करीब 1.3 फीसदी गिरकर 93.16 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कूड 1.6 फीसदी फिसलकर 85.70 डॉलर पर पहुंच गया। यह निवेशकों की मुनाफावसूली और आगामी अमेरिकी प्रतिबंधों की अनिश्चितता का परिणाम था। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई बताया है, जिसका लक्ष्य ईरान के आर्थिक संबंधों पर दबाव बढ़ाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान की मदद करने वाले देशों को चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ी है। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को दबाव और हताशा बताते हुए खारिज किया है और आर्थिक दबाव से निपटने के रास्ते तलाशने की बात कही।

निवेशकों को इशारु में सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है।

आईपीओ खुलने आईपीओ बंद	कंपनी का नाम	की तारीख	फेस वैल्यू
प्राइस बैंड	रिटेल प्राइस बैंड	इश्यू साइज	1सिम्बायोटेक फार्मालैब
24 अगस्त	27 अगस्त	₹ 9 36 -	₹ 938-₹988
₹ 986	1,757 करोड़	24 अगस्त	27 अगस्त
₹131-₹138	₹ 1 21 -	₹128	₹582.80 करोड़
3	हाई-टेक इंजीनियर्स	24 अगस्त	27 अगस्त
₹50-₹53	₹45-₹48	₹135.73	करोड़
4	मधुर निट क्राफ्ट्स	24 अगस्त	27 अगस्त
₹95-₹100	₹ 8 5 -	₹90	₹53.27 करोड़
5	एबीएच हेल्थकेयर	24 अगस्त	27 अगस्त
₹96-₹102	₹ 8 6 -	₹92	₹34.98 करोड़
6	अनु प्रोजेक्ट्स	25 अगस्त	28 अगस्त
₹94-₹99	₹84-₹89	₹175.06	करोड़
7	सुमैक्स इंजीनियरिंग	25 अगस्त	28 अगस्त
₹95-₹101	₹ 8 5 -	₹91	₹53.40 करोड़
8	ल्युमिनो इंडस्ट्रीज	27 अगस्त	31 अगस्त
₹78-₹82	₹73-₹77	₹ 7 0 0	करोड़
9	क्रिक फॉरेंसिक	सॉल्यूशंस	27 अगस्त
₹10	₹ 8 5 -	₹90	₹75-₹80
₹50.77	करोड़	नोट-	सिम्बायोटेक फार्मालैब, स्काईवेज एयर सर्विसेज, हाई-टेक इंजीनियर्स, मधुर निट क्राफ्ट्स और एबीएच हेल्थकेयर के आईपीओ की तारीखें और प्राइस बैंड उपलब्ध आईपीओ कैलेंडर के अनुसार हैं।

पेज एक का शेष

मानव और वन्यजीव संघर्ष को समाप्त...

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्रशर संचालन, जंगल क्षेत्रों में कोयला मिलने तथा उत्खनन जैसी गतिविधियों के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और आवागमन प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में विकास कार्यों और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन कायम करते हुए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि हाथी कॉरिडोर वाले क्षेत्रों में यदि सड़क निर्माण आवश्यक हो तो एलिवेटेड रोड जैसी तकनीक का उपयोग किया जाए, ताकि हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों के आवागमन में बाधा न आए। साथ ही, वन्यजीवों के लिए पसंदीदा एवं उपयोगी खाद्य प्रजातियों के पौधों का अधिकाधिक रोपण कराया जाए, ताकि उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और वन संपदा आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। इसके संरक्षण के साथ विकास के बीच संतुलन कायम करना सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से केंपा के तहत संचालित और प्रस्तावित योजनाओं की अद्यतन स्थिति, उपलब्ध राशि, व्यय, कार्यों की गुणवत्ता एवं जमीनी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जहां भी कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, वहां जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मानव एवं वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।विशेषकर हाथियों के आवागमन और उनके संपावित हमले से बचाव के लिए रामगढ़, बोकारो और चाकुलिया सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में थर्मल बेस एवं इंफ्रारेड कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। इन कैमरों के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों और आवागमन की पूर्व जानकारी प्राप्त हो सकेगी। टावर पर लगे कैमरों से हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही हूटर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अलर्ट जारी किया जाएगा। साथ ही, संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के मोबाइल नंबर रजिस्टर किए जा रहे हैं, ताकि हाथियों की गतिविधि की जानकारी उन्हें रियल टाइम मैसेज के माध्यम से तत्काल मिल सके। इसकी ऑनलाइन सूचना संबंधित विभागीय कार्यालय को भी प्राप्त होगी, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। विभागीय अधिकारियों ने पीपीटी प्रजेन्टेशन के माध्यम से इन तकनीकों पहल की कार्यप्रणाली, निगरानी व्यवस्था और संभावित लाभों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी।

यह पहल मानव जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने ...

अमित शाह ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने भगोड़ों को वापस लाकर मुकदमों में तेजी लाने और अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने यूएपीए से जुड़े मामलों की जांच के लिए व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने एमएस सीप्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाओं के एआई आधारित विश्लेषण के जरिए विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा। गृह मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन के दूसरे दिन सब-परियल सिस्टम से पैदा होने वाले खतरों और उनसे निपटने के उपायों, ब्लू इकोनॉमी की सुरक्षा, सूचना युद्ध के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव तथा जैव-सुरक्षा के लिए जरूरी ढांचे पर चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन 2021 से हर साल हाइड्रिड प्रारूप में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को साथ लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों का समाधान तलाशना है।

